



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 22, 1977/आश्विन 30, 1899

No. 43]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22, 1977/ASVINA 30, 1899

इस भाग में सिन्धु पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS  
(Department of Company Affairs)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1977

New Delhi, the 3rd October, 1977

क्र०अ० 3259.—एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा स० दि अमिट प्रोडक्ट्स लिमिटेड के, इस धारा के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 245/70) के विलोपन को इस प्रविबन्ध के आधार पर अधिसूचित करती है कि यह विलोपन केवल उस समय तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि कम्पनी, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2(र) की सीमा से परे रहे तथा यह कम्पनी के किसी ऐसे कार्य कलाप के प्रारम्भ कर बिना जाने पर, जिससे कि वह अधिनियम की धारा 2(र) में दिए गए एक उपक्रम की परिभाषा को आकर्षित करती हो, के तुरन्त स्थगन हो निष्प्रभावी हो जाएगा।

S.O. 3259.—In pursuance of sub-section (3) of section 25 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s The Amit Products Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 245/70) subject to the condition that the cancellation will be effective only until such time that the company continues to be outside the purview of section 2(v) of the M. R. T. P. Act and will be automatically in-effective no sooner than the Company starts any other activity which would attract the definition of an undertaking given in section (v) of the Act.

[सं० 2/23/76-एम-2]  
सी० खुशालदास, उप सचिव

[F. No. 2/23/76-M.II]  
C. KHUSHALDAS, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

## (बैंकिंग प्रभाग)

कां०आ० 3260.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० एल० जैन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-12/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ 4-12/75-ए० सी०]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th September, 1977

## BANKING DIVISION

S.O. 3260.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-12/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri S. L. Jain as the Chairman of the Jaipur Nagpur Aanchalik Gramin Bank, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-12/75-AC]

कां०आ० 3261.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० के० खन्ना की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-14/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ 4-14/75-ए० सी०]

S.O. 3261.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-14/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri S. K. Khanna as the Chairman of the Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-14/75-AC]

कां०आ० 3262.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्रथमा बैंक, मुरादाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० दस्तगीर की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-15/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-15/75-ए० सी०]

S.O. 3262.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-15/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri S. R. Dastgir, Chairman of the Prathma Bank, Moradabad, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-15/75-AC]

कां०आ० 3263.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उ० प्र०) के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० एन० राय की नियुक्ति विषयक भारत सरकार राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-58/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-58/76-ए० सी०]

S.O. 3263.—In exercise of the powers conferred by section 11, of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-58/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri B. N. Rai, as the Chairman of the Bhagirath Gramin Bank, Sitapur (U.P.), namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-58/76-AC]

कां०आ० 3264.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक, मलप्पुरम के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० कृष्णाकर शेट्टी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-60/76 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-60/76-ए० सी०]

**S.O. 3264.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F 4-60/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri A. Karunakara Shetty, as the Chairman of the South Malabar Gramin Bank, Malappuram, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-60/76-AC]

**क्र० प्रा० 3265.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोतीहारी के अध्यक्ष के रूप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-69/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 गितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० - 4-69/75-ए० सी०]

**S.O. 3265.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-69/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Shiv Sharma as the Chairman of the Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977", the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-69/75-AC]

**क्र० प्रा० 3266.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक, धारा के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० के० जैन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-70/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 गितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० एफ० 4-70/75-ए० सी०]

**S.O. 3266.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-70/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri P. K. Jain, as the Chairman of the Bhojpur Rohtas Gramin Bank, Arrah, namely :

In the said notification, for the figures letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-70/75-AC]

**क्र० प्रा० 3267.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जम्मू रूरल बैंक, जम्मू के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० कोतवाल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-72/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 गितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-72/75- ए० सी०]

**S.O. 3267.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-72/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri S. R. Kotwal, as the Chairman of the Jammu Rural Bank, Jammu, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-72/75-AC]

**क्र० प्रा० 3268.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तुंग भद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्गारी के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० ए० प्रभु को नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-73/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 गितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 4-73/75 ए० सी०]

**S.O. 3268.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-73/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri B. A. Prabhu, as the Chairman of the Tungabhadra Gramin Bank, Bellary, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-73/75-AC]

**क्र० प्रा० 3269.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मयूरथी ग्रामीण बैंक, मुरी के अध्यक्ष के रूप में श्री के० एम० बतर्जी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-75/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 गितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-75/76- ए० सी०]

**S.O. 3269.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-75/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri K. S. Banerjee, as the Chairman of the Mayurakshi Gramin Bank, Suri, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-75/76-AC]

**क्र० आ० 3270.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कटक ग्राम्य बैंक, कटक के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वरूप चन्द्र दाम की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-76/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-76/76-ए० सी०]

**S.O. 3270.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-76/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Swarup Chandra Dash, as the Chairman of the Cuttack Gramya Bank, Cuttack namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-76/76-AC]

**क्र० आ० 3271.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुलतानपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश प्रसाद दुबे की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-77/76 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-77/76 ए० सी०]

**S.O. 3271.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-77/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Jagdish Prasad Dubey, as the Chairman of Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-77/76-AC]

**क्र० आ० 3272.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्राग्ज्योतिष गांधोलिया बैंक नलवाडी के अध्यक्ष के रूप में श्री जी० सी० कालिता की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-79/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-79/75-ए० सी०]

**S.O. 3272.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-79/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri G. C. Kalita, as the Chairman of the Pragjyotish Gaonlia Bank, Nalbari, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words, "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-79/75-AC]

**क्र० आ० 3273.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बिलामपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलामपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० एम० शारदा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-79/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-79/76-ए० सी०]

**S.O. 3273.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-79/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri H. M. Sharda, as the Chairman of the Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, Bilaspur, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-79/76-AC]

**क्र० आ० 3274.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मगध ग्रामीण बैंक, गया के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रमोद के० प्रसाद की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-80/77 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-80/76-ए० सी०]

**S.O. 3274.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-80/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri R. K. Prasad as the Chairman of the Magadh Gramin Bank, Gaya, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-80/76-AC]

**क्र० आ० 3275.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा ग्रेन्थवाटी ग्रामीण बैंक, सीकर के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० जी० पुरी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-81/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-81/76-ए० सी०]

**S.O. 3275.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-81/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri R. G. Puri as the Chairman of the Shekhawati Gramin Bank, Sikar, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-81/76-AC]

**क्र० आ० 3276.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मारवाड़ ग्रामीण बैंक पाली के अध्यक्ष के रूप में श्री बलराम मिश्र की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-82/76 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-82/76-ए० सी०]

**S.O. 3276.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-82/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Balram Mishra, as the Chairman of the Marwar Gramin Bank, Pali, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-82/76-AC]

**क्र० आ० 3277.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रायमासीमा ग्रामीण बैंक, कुड्डापेठ के अध्यक्ष के रूप में श्री कृपा सागर कुण्डे की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-83/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-83/76-ए० सी०]

**S.O. 3277.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-83/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Kurupassagar Kunde, as the Chairman of the Royalaseema Gramina Bank, Cuddapah, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-83/76-AC]

**क्र० आ० 3278.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला के अध्यक्ष के रूप में श्री मानबेन्द्र सेन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-84/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों अक्षरों, और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-84/75-ए० सी०]

**S.O. 3278.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-84/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Manabendra Sen as the Chairman of the Tripura Gramin Bank, Agartala, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-84/75-AC]

**क्र० आ० 3279.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री विशाख ग्रामीण बैंक, श्री काकुलम के अध्यक्ष के रूप में श्री डी० आर० के० पटनायक की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-84/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-84/76-ए० सी०]

**S.O. 3279.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-84/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri D. R. K. Patnaik as the Chairman of the Sri Vishakha Gramseena Bank, Srikukulam, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-84/76-AC]

**क्र० आ० 3280.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० सी बुद्धिराज को नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राज्य और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-85/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० एफ० 4-85/75-ए० सी०]

**S.O. 3280.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-85/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri R. C. Budhiraja as the Chairman of the Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-85/75-AC]

**क्र० आ० 3281.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया के अध्यक्ष के रूप में श्री के० एन० शुक्ल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राज्य और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-85/76 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-85/76-ए० सी०]

**S.O. 3281.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-85/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri K. N. Shukla, as the Chairman of the Kosi Kshetriya Gramin Bank, Purnea, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-85/76-AC]

**क्र० आ० 3282.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० जी० बालगोपाल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राज्य और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-86/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-86/76-ए० सी०]

**S.O. 3282.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-86/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of the Shri H. G. Balagopal as the Chairman of the Cauvery Gramseena Bank, Mysore, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977", the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-86/76-AC]

**क्र० आ० 3283.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगीर के अध्यक्ष के रूप में श्री मोलक बिहारी सारंगी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राज्य और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-86/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-86/75-ए० सी०]

**S.O. 3283.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-86/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Golak Bihari Sarangi as the Chairman of the Bolangir Aanchalik Gramya Bank, Bolangir, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977", the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-86/75-AC]

**क्र० आ० 3284.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मालप्रभा ग्रामीण बैंक, आरवार के अध्यक्ष के रूप में श्री एम० सी० इनामदार की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राज्य और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-87/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-87/76-ए० सी०]

**S.O. 3284.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-87/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri M. V. Inamdar, as the Chairman of the Malaprabha Gramina Bank, Dhurwar, namely:

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-87/76-AC]

**क्र० आ० 13285**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली के अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेन्द्र महन्ती की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-87/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-87/75-ए० सी०]

**S.O. 3285.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-87/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Surendra Mahanty, as the Chairman of the Puri Gramya Bank, Pipli, namely:

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-87/75-AC]

**क्र० आ० 3286.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक जेपूर के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० नायक की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-88/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-88/76-ए० सी०]

**S.O. 3286.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-88/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri P. Nayak as the Chairman of the Koraput-Panchabati Gramya Bank, Jeypore, namely:

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-88/76-AC]

**क्र० आ० 3287.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बलिया ग्रामीण बैंक, बलिया के अध्यक्ष के रूप में श्री सी० धार० कश्यप की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-89/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-89/76-ए० सी०]

**S.O. 3287.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-89/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri D. R. Kathuria, as the Chairman of Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia, namely:

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-89/76-AC]

**क्र० आ० 3288.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री रघुबीरचन्द खन्ना की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-90/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-90/75-ए० सी०]

**S.O. 3288.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-90/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Raghbir Chand Khanna, as the Chairman of the Furrakhabad Gramin Bank, Furrakhabad, namely:

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-90/75-AC]

**क्र० आ० 3289.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० एम० दमोदरन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-90/76 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-90/76-ए० सी०]

**S.O. 3289.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-90/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri A. I. Damodaran Nair, as the Chairman of the North Malabar Gramin Bank, Cannanore, namely :

In the said notification for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-90/76-AC]

**क्र० आ० 3290.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ के अध्यक्ष के रूप में श्री हसन किशवई की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-91/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 नितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-91/75-ए० सी०]

**S.O. 3290.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-91/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Hasan Kidwai, as the Chairman of the Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh, namely :

In the said notification, for the figures letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-91/75-AC]

**क्र० आ० 3291.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली के अध्यक्ष के रूप में श्री श्याम चन्द्र सोनी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-92/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 नितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-92/75-ए० सी०]

**S.O. 3291.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-92/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Shyam Chandra Soni, as the Chairman of the Rae Bareilly Kshetriya, Gramin Bank, New Delhi.

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-92/75-AC]

**क्र० आ० 3292.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी के अध्यक्ष के रूप में श्री कंवर वीरेन्द्र मिश्र की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-93/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 नितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-93/75-ए० सी०]

**S.O. 3292.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-93/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Kanwar Virendra Singh Gupta as the Chairman of the Barabanki Gramin Bank, Barabanki namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977", the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-93/75-AC]

**क्र० आ० 3293.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बाकुरा के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रताप चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-94/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 नितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-94/75-ए० सी०]

**S.O. 3293.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-94/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Pratap Chakraborty as the Chairman of the Mallabhum Gramin Bank, Bankura, namely :

In the said notification, for the figures, letters, and words "30th September, 1977", the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-94/75-AC]

**क्र० आ० 3294.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संथाप परगना ग्रामीण बैंक, दुमला के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० के० घोष की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-134/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 नितम्बर, 1977 के अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-134/76-ए० सी०]

**S.O. 3294.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of



Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-134/76-AC, dated the 30th March, 1977 relating to the appointment of Shri B. K. Ghosh as the Chairman of the Santhal Parganas Gramin Bank, Dumka, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-134/76-AC]

क्रा० प्रा० 3295.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी के अध्यक्ष के रूप में श्री के० एस० राजपूत की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-136/76—ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 संकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 विषम्बर, 1977 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-136/76-ए० सी०]

S.O. 3295.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-136/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri K. S. Rajput, as the Chairman of the Himachal Gramin Bank, Mandi, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-136/76-AC]

क्रा० प्रा० 3296.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रीवा-सिधी ग्रामीण बैंक, रीवा के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० डी० नारंग की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-139/76—ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 संकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 विषम्बर, 1977 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-139/76-ए० सी०]

सी० थार० विस्वाम, उप-सचिव

S.O. 3296.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-139/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri B. D. Narang, as the Chairman of the Rewa-Sidhi Gramin Bank, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-139/76-AC]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

94 GI/77—2

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1977

क्रा० प्रा० 3297.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (5) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के निदेशक श्री हितेन भाया को 3 अक्टूबर, 1977 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 19(69) आई० एफ० 1/77]

वी० के० शुंगलू, निदेशक

New Delhi, the 3rd October, 1977

S.O. 3297.—In pursuance of sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri Hiten Bhaya, Director Indian Institute of Management, Calcutta as the director of the Industrial Development Bank of India with effect from the 3rd October, 1977.

[No. F. 10(69) IF. I/77]

V. K. SHUNGLU, Director

### उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मद्रास

मद्रास, 30 सितम्बर, 1977

सीमाशुल्क

क्रा० प्रा० 3298.—सीमाशुल्क, अधिनियम 1962 के उप-खण्ड (अ) खण्ड 152 के अन्तर्गत, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा) नई दिल्ली से जारी की गयी अधिसूचना संख्या 79/सीमाशुल्क VII तारीख 18 जुलाई 1975 में दिये हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद शुल्क समाहर्ता, मद्रास, जो वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग से अधिसूचना संख्या 37 सीमाशुल्क दिनांक 1 फरवरी, 1963 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के कार्यालय के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत "सीमाशुल्क समाहर्ता भी नियुक्त है" तमिलनाडु राज्य के नार्थ प्रारकाड जिले में वनियम्बाडी तालूक के "सोलूर ग्राम" को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के खण्ड 9 के अन्तर्गत (1962 का 52) "भाण्डागार स्टेशन" घोषित करते हैं।

[सं० सी० नं० VIII/40/8/77 सीमाशुल्क नीति]

ए० जे० राव, समाहर्ता

The Madras Central Excise Collectorate, Madras

Madras, 30th September, 1977

CUSTOMS

S.O. 3298.—In exercise of the powers conferred by Notification No. 79/Customs VII dated 18th July, 1975 issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, the Collector of Central Excise, Madras also appointed as "Collector of Customs" within the jurisdiction of the Madras Central Excise Collectorate by Government of India in Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 37 Customs dated the 1st February, 1963 hereby declares SOLUR VILLAGE of Vaniambadi Taluk, North Arcot District in the State of Tamil Nadu to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[C. No. VIII/40/8/77 Cus. Pol.]

I. J. RAO, Collector

**केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**

नई दिल्ली, 4 जून, 1977

आय-कर

क्रा० प्रा० 3299.—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679/फा० सं० 187/2/74—घाई टी (ए 1), तारीख 20 जुलाई, 1974 में उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

I. इससे उपाबद्ध अनुसूची के क्रम सं० 21-ब तमिलनाडु III मद्रास के सामने स्तंभ 3 में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी,

“13 पुडुकोट्टई सर्किल।”

II. इससे उपाबद्ध अनुसूची के क्रम सं० 21-ब तमिलनाडु, मद्रास के सामने स्तंभ 3 में क्रम सं० 10 के सामने की विद्यमान प्रविष्टि अर्थात् “पुडुकोट्टई सर्किल” का लोप किया जाएगा। क्रम संख्या 11 से 16 को क्रमशः 10 से 15 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

यह अधिसूचना 4-6-1977 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1801/फा० सं० 187/13/77-घाई टी (ए 1)]

एम० शास्त्री, प्रवर सचिव

**CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

New Delhi, the 4th June, 1977

**INCOME-TAX**

S. O. 3299.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its notification No. 679 (F. No. 187/2/74-IT(AI)) dated the 20th July, 1974 as amended from time to time :—

I. Against S. No. 21-B Tamil Nadu-III, Madras under column 3 of the Schedule appended thereto, the following entry shall be added :

13. Pudukottai Circle.

II. Against S. No. 21-C Tamil Nadu-IV, Madras under column 3 of the Schedule appended thereto, the existing entry against Serial Number 10 viz., Pudukottai Circle shall be deleted. Serial Number 11 to 16 shall be re-numbered 10 to 15.

This notification shall come into force on the 4-6-1977.

[No. 1801/F. No. 187/13/77-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

**वाणिज्य मंत्रालय**

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

क्रा० प्रा० 3300.—महेश्वरी महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि०, घाटकोपर, कण्डीवली, बम्बई को वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस संख्या पी/डी/2197910, दिनांक 27-4-74 के अनुसार कच्चा माल तथा संयंत्रों को आयात करने के लिए 3,46,223/- रुपए मात्र के लिए भारदोषी आयात लाइसेंस संख्या पी/एल/1772769/0, दिनांक 31-3-75 प्रदान किया गया था।

आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1976-77 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ी जाने वाली कांडिका 320 के अन्तर्गत उन्होंने एक शपथपत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने यह शपथ की है कि पूर्वोक्त लाइसेंस की शर्तों प्रतिया (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति) किसी भी सीमा शुल्क सदन के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल ही उपयोग में लाए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। पार्टी ने उक्त लाइसेंस (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति) के पूर्ण मूल्य 3,46,223/- रुपए मात्र के लिए अनुमति प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि मूल लाइसेंस यदि बाद में प्राप्त हो गया तो हम कार्यालय को वापस लौटा दिया जाएगा।

मैं गन्तुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस संख्या पी/एल/1772769/0, दिनांक 31-3-75 (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों) खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। अतः (अद्यतन तथा संशोधित) आयात नियंत्रण आदेश 1955, दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर, मैं पूर्वोक्त लाइसेंस (दोनों सीमा शुल्क तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों) को एतद्वारा रद्द करने का आदेश देता हूँ। पूर्ण मूल्य 3,46,223/- रुपए मात्र के लिए पूर्वोक्त लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति) की अनुमति प्रतिया खलस से जारी कर दी गई हैं।

[सि० सं० इन्जो० 258/जेएस-74/एससी-2/सीएलए से जारी]

एम० जी० गोम्बर, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

**MINISTRY OF COMMERCE****OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF****IMPORTS & EXPORTS****CANCELLATION ORDER**

New Delhi, the 31st January, 1977

S. O. 3300.—M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Ghatkopar, Kandivali, Bombay were granted REP import licence No. P/L/1772769/C dated 31-3-1975 for Rs. 3,46,223 only for import of Raw Materials and Components as per A/U licence No. P/D/2197910 dated 27-4-1974.

They have filed an affidavit as required under para 320 read with Appendix 8 of the ITO Hand Book of Rules & Procedure 1976-77 wherein they have sworn in that both copies (Customs Purposes & Exchange Control) of the aforesaid licence has been lost/misplaced without having been registered with any Customs House & utilised at all. The firm have applied for duplicate copies (Customs Purposes & Exchange Control) of the said licence for the full value of Rs. 3,46,223/- only and given an undertaking to return the original licence to this office if traced out later on.

I am satisfied that the original licence No. P/L/1772769/C dated 31-3-1975 (both Customs Purposes Copy & Exchange Control Copy) has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the power conferred on me under clause 9(c) of the Import Control Order 1955 dated 7-12-1955 (as amended up to date), I hereby order the cancellation of the aforesaid licence (both Customs & Exchange Control Copies).

Duplicate copies of the above mentioned licence (Customs Purposes & Exchange Control) for the full value of Rs. 3,46,223/- only has been issued separately.

[Issued from file No. Engg. 258/JS-74/SC II/CLA]

M. G. GOMBER, Dy. Chief Controller  
for Jt. Chief Controller.

## मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1977

क्र० आ० 3301.—सर्वश्री मार्शल सन्स एण्ड कं. मैन्युफैक्चरिंग लि० संख्या 9 सेकेण्ड लाइन बीच, मद्रास-600001 का स्वीडिश साब से संलग्न सूची के अनुसार कच्चे माल/संघटकों के आयात के लिए 93,100/- रुपए के लिए लाइसेंस संख्या पी/डी/2202328/आर/एम डब्ल्यू/57/एच/41-42, दिनांक 12-9-75 प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने पूर्वोक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति के अनुलिपि के लिए इस आधार पर निवेदन किया है कि उन से मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति, सीमाशुल्क मदन, मद्रास, में पंजीकृत कराने के पश्चात् खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी ने आगे यह सूचना दी है कि लाइसेंस में 13,437/- रुपए की धनराशि शेष है।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2202328/दिनांक 12-9-75 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

4. सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि अलग में जारी की जा रही है।

[संख्या मके/एम-1(1)/एम-76/आर.एम-4/697]

एन० ए० कोहली, उप-मुख्य नियंत्रक  
कृते मुख्य नियंत्रकoffice of the Chief Controller of Imports and Exports  
New Delhi

ORDER

New Delhi, the 1st September, 1977

S.O. 3301.—M.s. Marshall, Sons & Co. Mfg. Limited, No. 9 Second Line Beach, Madras-600001 were granted import licence No. P/D-2202328/R/SW/57/H/41-42 dated 12-9-1975 for import of Raw materials/components as per list attached to it valued at Rs. 93,100/- from Swedish Credit.

2. They have requested for the issue of Duplicate Customs purposes copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost or misplaced after having been registered with the Customs, Madras. It has been further reported by the licence that the licence had an unutilised balance of Rs. 13,437/-.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes copy of Import Licence No. P/D-2202328 dated 12-9-1975 has been lost or misplaced and hence directs that a Duplicate Customs Purposes copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy is hereby cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[File No. Mach/M-1(1)/AM76/RM4/697]  
N. A. KOHLY, Dy. Chief Controller.

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

क्र० आ० 3302 — दि० पी० एण्ड ई० कार्पोरेशन इण्डिया लि०, नई दिल्ली का 2,94,700/- रुपए जापान मे इकोराकंडर फिश पाउडर का आयात करने के लिए लाइसेंस संख्या जी/टी/2500180 दिनांक

26-2-69 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियों की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनसे उक्त लाइसेंस की दोनों मूल प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि लाइसेंस सीमाशुल्क सवन, बम्बई में पंजीकृत कराया गया है और प्रांशिक रूप में उपयोग में लाया गया है। शेष धनराशि 19,674/- रुपए के लिए अब अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या जी/टी/2500180/दिनांक 26-2-69 की दोनों प्रतियां खो गई हैं तथा निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियां उनको जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की दोनों प्रतियां एतद्वारा रद्द की जाती है।

लाइसेंस संख्या जी/टी/2500180, दिनांक 26-2-69 की दोनों प्रतियां अलग में जारी की जा रही है।

[संख्या एस०टी०सी०/एम०आई०एस०सी०/68/77/68-69/

आर०एम०सेल/187]

ए० के० शर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 3302.—The P. & E. Corpn. of India Ltd., New Delhi were granted licence No. G/T/2500180, dated 26-2-69 for the Import of Echosounder Fish Finder etc. from Japan to the value of Rs. 2,94,700/-. They have requested for the issue of duplicate both copies of the above licence on the ground that are Original both copies of the above licence has been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence has been registered with Customs House Bombay and utilized partly. The duplicate copy now required is to cover the balance of Rs. 19,674/-.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that both the copies of licence No. G/T/2500180, dated 26-2-1969 have been lost and directs that both copies of the said licence should be issued to them. The both the copies of the licence are hereby cancelled.

Both copies of the licence No. G/T/2500180 dated 26-2-1969 are being issued separately.

[File No. STC/MISC-68-77/68-69/RM Cell/187]

A. K. SHARMA, Dy. Chief Controller.

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1977

क्र० आ० 3303.—सर्वश्री गर्बोरे प्लास्टिक प्रा० लि०, बम्बई को 26,07,895/- रुपए (छियालिस लाख सात हजार आठ सौ पंचानवे रुपए मात्र) के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2067147/एम/आईवी/51/एच/37-38, दिनांक 30-4-1974 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की मूल प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की मूल प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत करवाई गई थी और प्रांशिक रूप से उपयोग में लाई गई थी। यह 15,43,683/- रुपए के लिए उपयोग में लाई गई थी और दिनांक 18-8-1977 को उस पर 64,212/- रुपए की धनराशि शेष है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने अनिवारित मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, बम्बई, के सम्मुख विशिष्ट शपथ लेकर एक शपथ-पत्र

वांछित किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर सर्वश्री गरवारे प्लास्टिक प्रा० लि०, बम्बई को जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2067147/एस/आईवी/51/एच/37-38/सीजी-3, दिनांक 30-4-1974 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अब अलग से लाइसेंसधारी को जारी की जा रही है।

[संख्या सी जी-3/21/(105)/73-74/1511]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक,  
कृते मुख्य-नियंत्रक

### ORDER

New Delhi, the 1st October, 1977

**S.O. 3303.**—M/s. Garware Plastics Ltd., Bombay were granted an Import Licence No. P/CG/2067147/S/IB/51/H/37-38 dated 30-4-1974 for Rs. 46,07,895 (Rupees Fortysix lakhs seven thousand eight hundred and ninety five only). They have applied for issue of a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes was registered with the Customs authorities at Bombay and utilised partly. It was utilised for Rs. 45,43,683 and the balance available on it was Rs. 64,212 as on 18-8-1977.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly affirmed before the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Bandra, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the power conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy of licence No. P/CG/2067147/S/IB/51/H/37-38/CG. III dated 30-4-1974 issued to M/s. Garware Plastics Pvt. Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licence.

[No. CG. III/21/(105)/73-74/1511]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller  
for Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय, मद्रास

मद्रास, 6 अगस्त, 1977

आदेश

**क्रा० आ० 3304.**—सर्वश्री डब्ल्यू. एस. इनसुलेटर्स प्रा० लि०, पोरूर, मद्रास-602104 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से उक्त लाइसेंस के लिये संलग्न अनुबन्ध में यथावर्णित कच्चे मास एवं संघटकों के आयात के लिये लाइसेंस संख्या पी०/एम०/2779916/सी०/एक्स/57/एम०/41-42 दिनांक 10-12-75 जारी किया गया था। उक्त लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी करने के लिये अब इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मुद्रा विनियम प्रति मद्रास सीमा शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत कराने के और अंशतः उपयोग में लाने के पश्चात् डाक मार्ग में खो गयी है। कुल मूल्य जिसके लिये लाइसेंस जारी किया गया था वह 1,27,217 रुपये है और कुल सेय मूल्य जिस को पूरा करने के लिये अब अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह 16,226.00 रुपये है। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक फर्म ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पी०/एम०/2779916/सी०/एक्स/57/एम०/41-42 दिनांक 10-12-75 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण

प्रति खो गई है और निवेश देता हूँ कि आवेदन को लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिये। आयात लाइसेंस संख्या पी०/एम०/2779916/सी०/एक्स/57/एम०/41-42, दिनांक 10-12-75 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति को एतद्वारा किया जाता है।

[मिसिल संख्या ई०/जी/एडवा ला०/2/ओडी-75/म्रा ई० पी०-2 से जारी]

आई० ए० रशीद, उप-मुख्य नियंत्रक,

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports,  
Madras

### ORDER

Madras, the 6th August, 1977

**S.O. 3304.**—M/s. W. S. Insulators of India Limited, Porur, Madras-602104 were issued an import licence No. P/M/2779916/C/XX/57/M/41-42 dt. 10-12-1975 for import of raw materials and components as detailed in the annexure attached to the said licence under General Currency Area. The said licence holder have now applied to this office for the issue of Duplicate of the Exchange Control Copy of the said import licence on the ground that the Exchange Control Copy of the licence has been lost in postal transit after having been registered with Madras Custom House and utilised partly. The total amount for which the licence was issued is Rs. 1,27,217 and the total amount for which the duplicate copy is now required is to cover the balance Rs. 16,226.00. In support of their contention the applicant firm has filed an affidavit.

I am satisfied that the original Exchange Control Copy of the Import licence No. P/M/2779916/C/XX/57/M/41-42/dt. 10-12-1975 has been lost and direct that a duplicate Exchange Control Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy of the import licence No. P/M/2779916/C/XX/57/M/41-42/dt. 10-12-75 is hereby cancelled.

[Issued from file No. Engg/Adv. Lic./2/OD. 75/REP.III]

L. A. RASHID, Dy. Chief Controller

### पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1977

**क्रा० आ० 3305.**—पेट्रोलियम और खनिज पाइपसाइन (घूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा (2), खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम-1 में दिये हुए प्राधिकारी के कथित अधिनियम के अधीन अनुसूची के कालम 2 के अनुरूप लिखित क्षेत्रों के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

### अनुसूची

प्राधिकारी और पता	क्षेत्र
(1)	(2)

सम्पर्क अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस विभाग, महाराष्ट्र राज्य  
महाराष्ट्र सरकार राजस्व तथा धन विभाग, बम्बई

400032

[संख्या 12017/1/74-एल एंड एस/प्रोडक्शन]

## MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 26th September 1977

**S. O. 3305.**—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column 1 of the Schedule below to perform the functions of the competent authority under the said Act within the areas mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said Schedule.

## SCHEDULE

Authority and Address	Area
Liason Officer, Oil and Natural Gas Commission, Government of Maharashtra, Revenue and Forests Department, Bombay-400032.	State of Maharashtra.

[No. 12017/1/74-L&amp;L/Prod.]

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1977

**क्र० प्रा० 3306.**—पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (2), खण्ड (क) के अनुमरण में और भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की दिनांक 22 जनवरी, 1972 की अधिसूचना संख्या क्र० प्रा० 389 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में दिये हुए प्राधिकारी के कथित अधिनियम के अधीन अनुसूची के कालम (2) में प्रविष्टि के अनुरूप लिखित क्षेत्रों के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

प्राधिकारी और पता	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)
कामिक तथा प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा इंडियन पश्चिम बंगाल प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरी तथा पाइप लाइन प्रभाग) कलकत्ता-700020	

[संख्या 12017/1/74-एल एण्ड एल/प्रोडक्शन]

New Delhi, the 28th September, 1977

**S. O. 3306.**—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals No. S.O. 389 dated the 22nd January, 1972, the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column 1 of the Schedule below to perform the functions of the competent authority under the said Act, within the areas mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said Schedule.

## SCHEDULE

Authority and Address	Areas
Personnel & Admn. Officer, C/o. Indian Oil Corporation Ltd. (Refineries and Pipelines Division) Calcutta-700020.	West Bengal

[No. 12017/1/74-L &amp; L/Prod.]

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

**क्र० प्रा० 3307.**—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के क्र० प्रा० सं० 664 के अन्तर्गत अधिसूचना 12020/1/77-प्रोडक्शन-1, दिनांक 31-1-77 जो धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत तहसील महवा जिला सवाई माधोपुर की उस अधिसूचना से पाबंद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिये भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 26-2-77 में पृष्ठ संख्या 832 से 835 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में "पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार पर अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) शब्द पढ़े जायेंगे।

[क्रमांक 12020/1/77-प्रोडक्शन-1]

## CORRIGENDA

New Delhi, the 29th September, 1977

**S.O. 3307.**—In para 3 of the Government of India Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/1/77/Prod. I dated 31-1-1977 issued under S. O. 664 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos. 832 to 835 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Mahwa District Sawai Madhopur specified in the schedule appended to that Notification, for the words "Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" the words "Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" shall be substituted.

[No. 12020/1/77-Prod.-I]

## शुद्धि-पत्र

**क्र० प्रा० 3308.**—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के क्र० प्रा० सं० 665 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/1/77-प्रोडक्शन-II दिनांक 31-1-77 जो धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तहसील टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर की उस अधिसूचना से पाबंद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिये भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 26-2-77 में पृष्ठ संख्या 835 से 838 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में "पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)" शब्द पढ़े जायेंगे।

[क्रमांक 12020/1/77-प्रोडक्शन II]

## CORRIGENDA

**S.O. 3308.**—In para 3 of the Government of India Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/1/77-Prod-II dated 31-1-1977 issued under S.O. 665 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos 835 to 838 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Todabhim District Sawai Madhopur specified in the schedule appended to that Notification, for the words "Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" the words "Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" shall be substituted.

[No. 12020/1/77-Prod.-II]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1977

का० आ० 3309.—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के का०आ० सं० 662 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/2/77-प्रोडक्शन-II दिनांक 28-1-77 जो धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत तहसील मालपुरा जिला टोंक की उस अधिसूचना से पावट्र अधिसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये भारत सरकार के राजपत्र भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 26-2-77 में पृष्ठ संख्या 822 से 831 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में "पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)" शब्द पढ़े जावेंगे।

[क्रमांक 12020/2/77-प्रोडक्शन I]

New Delhi, the 1st October, 1977

## CORRIGENDA

S.O. 3309.—In para 3 of the Government of India, Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/2/77-Prod-II dated 28-1-1977 issued under S.O. 662 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos 822 to 831 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Malpura District Tonk specified in the schedule appended to that Notification, for the words "Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" the words "Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" shall be substituted.

[No. 12020/2/77-Prod. I]

शुद्धि पत्र

का० आ० 3310.—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के का०आ० सं० 661 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/2/77-प्रोडक्शन-I दिनांक 28-1-77 जो धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत तहसील मथुरा जिला मथुरा की उस अधिसूचना से पावट्र अधिसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये भारत सरकार के राजपत्र भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 26-2-77 में पृष्ठ संख्या 819 से 822 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में "पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)" शब्द पढ़े जावेंगे।

[क्रमांक 12020/2/77-प्रोडक्शन-II]

टी० पी० सुब्रह्मण्यन, प्रवर सचिव

## CORRIGENDA

S.O. 3310.—In para 3 of the Government of India, Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/2/77-Prod. I dated 28-1-1977 issued under S.O. 661 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos. 819 to 822 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Mathura District Mathura specified in the schedule appended to that Notification, for the words "Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" the words "Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)" shall be substituted.

[No. 12020/2/77-Prod. II]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

का० आ० 3311.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के वीरमगम तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में क्षेत्रन स्थल सं० एम०पी०जे० से एन०के०ओ० से एम०पी०ई० तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उपखंड (1) की धारा (1) में निविष्ट कार्य दिनांक 23-2-76 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत मसम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त निधि को कार्य मसम की निधि अधिसूचित करते हैं।

## अनुसूची

एम०पी०जे० से एन०के०ओ० से एम०पी०ई० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य की समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम और भरागया	बालमामण	960	26-3-77	23-2-76

[संख्या 12020/5/77-प्रोडक्शन-I]

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 3311.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. No. SPJ to NKO to SPE in Viramgam Oil field in Gujarat State.

And whereas the oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-2-76

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

## SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SPJ to NKO to SPE

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of Publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum	Balsasan & Bhateria	960	26-3-77	23-2-76

[No. 12020/5/77-Prod. I]

का० आ० 3312.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोगता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० एस०डी०आर० से आर०ओ०यू० 207 से जी०जी०एस० 1 तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उपखंड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26-11-75 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोगता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त लिपि को कार्य सभा की लिपि अधिसूचित करने हैं।

#### अनुसूची

एस०डी०आर० से आर०ओ०यू० 207 से जी०जी०एस० 1 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राज-कार्य समाप्ति पत्र में प्रकाशन की तिथि	की तिथि
पेट्रोलियम	पुनसन	1893	11-6-77	26-11-75

[संख्या 12020/5/77-प्रोडक्शन-II]

क० धी० देशपाण्डे, गुजरात के लिये नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 3312.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. No. SDR to ROU 207 to GGS-I in Mehsana oil field in Gujarat State,

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act on 26-11-75.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

#### SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SDR to ROU 207 GGS-I

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum	Punasan	1893	11-6-77	26-11-75

[No. 12020/5/77-Prod. II]

K. V. DESHPANDE, Competent Authority Under the Act for Gujarat

#### उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1977

का० आ० 3313.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की देखभाल) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा, 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ-1 में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की संबंधी परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत, अपनी अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

#### सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों का प्रयोग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
महायक कलक्टर, प्रथम श्रेणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली	दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के स्वामित्ववादी/के द्वारा प्रजित या किराये पर लिए गए सरकारी स्थान।

[का० सं० 29(4)/77-एस एस आई (2)]

डी० एस० बावा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 13th October, 1977

S.O. 3313.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in Column-I of the Table below, being Gazetted Officer of Government to be estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table :—

#### TABLE

Designation of Officer	Category of public premises and local limits of jurisdiction
Assistant Collector, First Grade, Parliament Street, New Delhi.	Public premises owned/acquired or hired by the Delhi State Industrial Development Corporation Ltd., New Delhi.

[F. No. 29(4)/77-SSI(II)]

D. S. BAWA, Under Secy.

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर 1977

क्र० आ० 3314.—राजनयिक एवं कोमली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा (क) खंड (2) के अनुपालन में केन्द्र सरकार हमके द्वारा भारत का राजदूतावास बेहरीन में महायक, श्री महेश कुमार को तत्काल से कोमली अधिकारी का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[फाइल सं० टी० 4330/1/77]

एस० एन० गोयल, प्रवर सचिव

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th September, 1977

S.O. 3314.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri Mohinder Kumar, Assistant in the Embassy of India, Bahrain to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T. 4330/1/77]

S. N. GOEL, Under Secy.

## नागरिक पूर्ति तथा सहकारीता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

क्र०अ० 701(अ) 3315.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि दालों और खाने योग्य तेलों की मज्दारी बनाए रखने तथा उनका साम्यापूर्ण वितरण और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।

(3) इस आदेश के खंड 3 और 5, 10 अक्टूबर, 1977 को प्रवृत्त हो जाएंगे और गेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. परिभाषाएं:—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “व्यवहारी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी दाल या खाने योग्य तेल की खरीद, बिक्री या विक्रयार्थ भण्डारण के कारखाने में लगा हुआ है;

(ख) “उत्पादक” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दालों की दलाई के अथवा किसी खाने योग्य तेल को निकालने या उसके निष्कासन के कारखाने में लगा हुआ है;

(ग) “दाग” से अभिप्रेत है, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, लोबिया, राजमा या अन्य कोई दाग चाहे वह पूरी पूरी हो या भूमी सहित या भूमी रहित टूटी हुई हो;

(घ) “फुटकर व्यापारी” से ऐसी दालों या खाने योग्य तेलों का ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो थोक विक्रेता न हों;

(क) “राज्य आदेश” से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबन्धों के अधीन किसी राज्य सरकार या मध्य राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश जो तत्समय प्रवृत्त है, अभिप्रेत है;

(च) “बोकर विप्रेता” से दालों या खाने योग्य तेलों का ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो इन वस्तुओं को अन्य व्यवहारियों अथवा बड़ी मात्रा में खरीदने वाले उपयोक्ताओं के हाथ में बेचता है।

3. व्यवहारियों का अनुशासन:—किसी राज्य आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस खंड के प्रवृत्त होने से पन्द्रह दिन की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, कोई भी व्यक्ति दाल या खाने योग्य तेलों में व्यवहारी के रूप में कोई कारखाना, मिठाई किसी राज्य आदेश के अधीन दी गई अनुरोधों के निबन्धना और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार कारखाना करने के, नहीं करेगा यदि उसके पास दालों या खाने योग्य तेलों का स्टॉक नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक हो:

स्टॉक की सीमा

- (i) दालें सभी दालें, कुल मिलाकर 5 क्विंटल।  
(ii) खाने योग्य तेल जिसमें वनस्पति सभी खाने योग्य तेल, जिसमें वनस्पति भी है, कुल मिलाकर 5 क्विंटल।

4. दालें और खाने योग्य तेल अपने पास रखने पर निबन्धन:—कोई भी व्यवहारी नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक दालें या खाने योग्य तेल का स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी भी समय, इस खंड के प्रवृत्त होने से पन्द्रह दिन की अवधि के पश्चात्, न तो भण्डारण करेगा और न ही उसे अपने कब्जे में रखेगा:

क्विंटलों में स्टॉक सीमा

	थोक विक्रेता	फुटकर विक्रेता
(i) दालें	500 (सभी दालें कुल मिलाकर)	25 (सभी दालें कुल मिलाकर)
(ii) खाने योग्य तेल, जिसमें वनस्पति भी है।	150 (केवल वनस्पति) 200 (सभी खाने योग्य तेल, जिसमें वनस्पति नहीं है, कुल मिलाकर)	5 (केवल वनस्पति) 5 (सभी खाने योग्य तेल, जिसमें वनस्पति नहीं है, कुल मिलाकर)

5. विवरणियाँ:—खंड 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवहारी और प्रत्येक उत्पादक जिसके पास खंड 4 में थोक विक्रेता के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक दालों या खाने योग्य तेलों का स्टॉक है, दालों और खाने योग्य तेलों, जिनमें वनस्पति भी है, के स्टॉकों के सम्बन्ध में जो उसके पास है, ऐसे प्राधिकारों को और ऐसी रीति से पाक्षिक विवरणी भेजेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

6. राज्य आदेशों का लागू न होना:—किसी दालों या खाने योग्य तेलों के भण्डारण सम्बन्धी किसी भी राज्य आदेश के उपबन्ध ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होंगे जिनके लिए इस आदेश में विनिर्दिष्ट रूप में उपबन्ध किया गया है।

7. आदेश का कुछ मामलों में लागू न होना:—इस आदेश की कोई भी बात—

- (i) ऐसे निगम या कम्पनी को लागू नहीं होगी जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, अथवा;



(ii) ऐसी किसी केन्द्रीय स्तर या राज्य स्तर की सहकारी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो खालो या खाने योग्य तेलों के उत्पादन, उपादन, विक्रय, खरीद या वितरण में लगी हुई है।

टिप्पणी इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद भारत राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (ii) दिनांक 30 सितम्बर, 1977 में छप चुका है।

[फा० सं० 26 (16)/77-ई सी आर]

आदेश

फा०आ० 702(अ)/3316.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सरसों के तेल के साम्यापूर्ण वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपायेयता को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1 सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस आदेश का सक्षिप्त नाम सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त हो जायगा।

2 परिभाषा.—इस आदेश में, “व्यवहारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सरसों के तेल की खरीद, बिक्री या बिक्री के लिए भण्डारण के कारबार में लगा हुआ है।

3. वह कीमत जिस पर व्यवहारी बेच सकेगा—कोई भी व्यवहारी सरसों के तेल को इस रुपये प्रति किलोग्राम की फुटकर कीमत से, जिसमें भाधान की कीमत शामिल नहीं है, किन्तु कर सम्मिलित है, अधिक कीमत पर, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, न तो बेचेगा और न बेचने की प्रस्थापना करेगा।

टिप्पणी :—इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद, भारत राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (ii), दिनांक 30 सितम्बर, 1977 में छप चुका है।

[फा० सं० 26 (16)/77-ई सी आर]

टी० बालकृष्णन, समुक्त सचिव

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

फा०आ० 3317.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को एक सितम्बर, 1977 से 8 सितम्बर, 1977 तक उक्त बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है—

1 श्री बी० जी० कोणी

2 श्री एम० के० वर्मा

[फा० सं० 11/3/76-एफ० सी०]

ए० बी० नारायणन, उप सचिव

### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 3317.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of Rule 8 read with Sub-rule (1) of Rule 7 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory panel of the said Board at Bombay with effect from 1st September, 1977 upto 8th September, 1977:—

1. Shri B.G. Koshy.

2. Shri M.K. Verma.

[F. No. 11/3/76-FC]

A.V. NARAYANAN, Dy. Secy.

### पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

बंदोबस्त विंग

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1977

फा०आ० 3318.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की अपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में कार्य कर रहे बन्दोबस्त अधिकारी श्री प्रीतम सिंह को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रवर्ध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्रवर्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० ए० 36016/1/75-प्रशा० (राज०)/बं० वि०]

एच० के० टेकचन्दानी, अवसर सचिव

### MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

SETTLEMENT WING

New Delhi, the 17th September, 1977

S.O. 3318.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Pritam Singh, Settlement Officer in the Department of Rehabilitation, as Managing Officer for the purpose of performing the functions assigned to such Officer by or under the said Act.

[No. A-36016(1)/75-AGZ/SW]

H. K. TECKCHANDANI, Under Secy.

### कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

फा०आ० 3319—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीरा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1969 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों

की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

#### नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम जीरा श्रेणीकरण और चिह्ननांकन (संशोधन) नियम, 1977 है।

2. जीरा श्रेणीकरण और चिह्ननांकन नियम 1969 में, अनुसूची 2 में, स्तम्भ 1 में, श्रम संख्या 4 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या, प्रविष्टि और टिप्पण अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात्—

“5 अविनिर्दिष्ट श्रेणी, जैसा कि क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य करार हुआ।

टिप्पण—अविनिर्दिष्ट श्रेणी के अधीन जीरे का निर्यात, किसी विदेशी क्रेता के किसी पक्के आदेश प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहने हुए होगा जिसमें जीरे की अपेक्षित क्वालिटी और मात्रा उपदर्शित होगी और जो उस जीरे के मूल्य के संदाय की भी गारंटी देगा।”

[सं. एफ. 13-1/77-ए.एम.]

### MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 30th September, 1977

**S.O. 3319.**—The following draft of certain rules further to amend the Cumin Seeds Grading and Marking Rules, 1969, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified, will be considered by the Central Government.

#### DRAFT RULES

1. These rules may be called the Cumin Seeds Grading and Marking (Amendment) Rules, 1977.
2. In the Cumin Seeds Grading and Marking Rules, 1969, in Schedule II, in column 1, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number entry and note shall be inserted, namely:—

“5. Non-specified Grade : As agreed between buyer and exporter.

**Note.**—Export of Cumin Seeds under non-specified grade shall be subject to the production of a firm order from a foreign buyer which shall indicate the quality, and the quantity required, of the Cumin Seeds, and shall also guarantee the payment of the price of the Cumin Seeds.”

[No. F. 13-1/77-AM]

क्रां.सं. 3320.—मधु श्रेणीकरण और चिह्ननांकन नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, कृपि उपज

(श्रेणीकरण और चिह्ननांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षासुसार भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (श्रापीण विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या 1399 तारीख 1 अप्रैल 1976 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 17 अप्रैल, 1976, पृष्ठ 1495-1496 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतिया, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति तक, उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

और उक्त राजपत्र 17 अप्रैल, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मधु श्रेणीकरण और चिह्ननांकन (संशोधन) नियम 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 मधु श्रेणीकरण और चिह्ननांकन नियम 1970 में—

(1) नियम 6 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अनिर्दिष्ट, भारत सरकार के कृषि विपणन मन्त्रालय द्वारा निदेशित रीति से निम्नलिखित विशिष्टियां आदान पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाएंगी, अर्थात्—

(क) पैकर का नाम

(ख) जिस साट का वह मधु है, उसकी संख्या

(ग) पैकिंग की तारीख और स्थान

(घ) शुद्ध भार

(ङ) समाप्ति की तारीख

(2) अनुसूची 1 में,—

(क) श्रेणी अभिधान “श्रेणी क” के मामले, स्तम्भ 5 में, प्रविष्टि “8” के स्थान पर प्रविष्टि “5” रखी जाएगी,

(ख) श्रेणी अभिधान मानक के मामले,—

(i) स्तम्भ 5 में, प्रविष्टि “10” के स्थान पर, प्रविष्टि “5” रखी जायगी।

(ii) स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “60” के स्थान पर प्रविष्टि “65” रखी जाएगी।

[सं. फा. 13-10/75-ए.एम.]

ए. के. अग्रवाल, उप सचिव

**S.O. 3320.**—Whereas a draft of certain rules further to amend the Honey Grading and Marking Rules, 1970 was published as required by the section 3 of Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 1495-1496 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th April, 1976, with the notification of Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development), No. S.O. 1399, dated the 1st April, 1976 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th April, 1976 ;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called Honey Grading and Marking (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Honey Grading and Marking Rules, 1970,—

(i) in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly marked on the container in a manner directed by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, namely :—

- (a) Name of the packer ;
- (b) Lot number to which honey pertains ;
- (c) Date and Place of packing ;
- (d) Net weight ;
- (e) Date of expiry.”

(ii) in Schedule I,—

(a) against grade designation ‘Grade A’, in column 5, for the entry ‘8’, the entry ‘5’ shall be substituted ;

(b) against grade designation ‘Standard’,—

- (i) in column 5, for entry “10”, the entry “5” shall be substituted ;
- (ii) in column 8, for the entry “60”, the entry “65” shall be substituted.

[No. F. 13-10/75-A.M.]

A. K. AGARWAL, Dy. Secy.

### नौबहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

### व्यापार पोत

क्र.सं. 3321.—राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 3 और 4 के साथ पठित वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 218 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिये राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् —

1. नौबहन-प्रभारी मंत्री (पदेन) अध्यक्ष  
सदस्य
2. नौबहन महानिदेशक, बालचंद्र हीरा० मद्रस्य (पदेन)  
चंद मार्ग, जहाज भवन बंबई-400011
3. संयुक्त सचिव (नाविक कल्याण),  
नौबहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. सहायक वित्तीय पलाहकार, नौबहन  
और परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय  
(व्यय विभाग) का प्रतिनिधि ।
5. श्री अशोक नारायण, उप सचिव, श्रम  
मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. श्री एम० श्रीनिवासन, उप सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परि-  
वार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

7. श्री आर० के० मुधुभट्टी, पत्तन निवे- गुजरान सरकार के प्रतिनिधि ।  
शक, सांनिविभाग, गोधीनगर ।

8. कप्तान पी०के०आर० नय्यर, पत्तन केरल सरकार के प्रतिनिधि ।  
निदेशक, केरल राज्य, त्रिवेन्द्रम ।

9. मुख्य पत्तन अधिकारी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ।  
राज्य, बंबई ।

10. कप्तान के० के० एस० कुमारन, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ।  
पत्तन एवं अन्तर्देशीय जल परिवहन  
निदेशक, कारवाड ।

11. श्री पी० एन० बनरा, निदेशक, कलकत्ता पत्तन न्यास के  
जल विभाग, कलकत्ता पत्तन न्यास, प्रतिनिधि ।  
कलकत्ता ।

12. श्री एम० के० जार्ज, बंदरगाह मास्टर, कोचीन पत्तन न्यास के  
कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन । प्रतिनिधि ।

13. कप्तान पी० बलराम, उप संरक्षक, मद्रास पत्तन न्यास के प्रतिनिधि ।  
मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास ।

14. कप्तान पी० डी० गुप्ता, उप संरक्षक, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के  
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखा- प्रतिनिधि ।  
पत्तनम ।

15. कप्तान आर० डी० कोहली, कार्यकारी  
निदेशक, भारतीय नौबहन निगम  
लि० मिथिया हाउस, मेडल कामा रोड,  
बंबई-400021 ।

16. कप्तान बी० डी० कटारिया, निदेशक,  
मैसर्स सैविन सीम ट्रांसपोर्टेशन लि०  
15-ए, चन्द्रमुखी, नरीनर पार्क,  
बंबई- } जहाज स्वामियों के प्रतिनिधि

17. श्री टी० एस० नरायण, उप प्रबंधक,  
मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी  
लि० मिथिया हाउस, बंबई-400001

18. श्री एन० लतीफ, अध्यक्ष, स्वामियों  
या एजेंटों की समिति (कर्मोक्क)  
4-गुरजी बल्लभवास मार्ग, बैलाड  
एस्टेट, बंबई- } पोत स्वामियों के प्रतिनिधि

19. श्री एन० के० सेन, अध्यक्ष, कलकत्ता  
लाइनर्स सम्मेलन (कर्मोक्क) 16,  
स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता ।

20. श्री के० पी० कोलाह, महासचिव,  
मेरीटाइम यूनिन आफ इंडिया, नेशन-  
ल इन्डोरिस बिल्डिंग, 204 डा०  
डी०एन० रोड, बंबई-400001 ।

21. श्री लियू बारनेस, महासचिव, भारतीय  
राष्ट्रीय नाविक संघ, 1, गोम्रा स्ट्रीट,  
फोर्ट, बंबई ।

22. श्री याकूब एम० सेरांग, मारफत  
भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ, 4-  
गोम्रा स्ट्रीट, फोर्ट, बंबई ।

23. श्री नरेण चन्द्र भारद्वाज, मारफत  
भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ, 10/2-  
बी, कवितीर्थ सारनी, कलकत्ता-23 ।

24. श्री विलास मांजरेकर, महासचिव,  
जहाजी मजदूर यूनिन, कामगार  
सदन, नवाब टैंक रोड, मजगांव, बंबई-  
400010 ।

25. श्री बी०पी० कादम }

26. श्री पी० ध्यागराजन }

संयुक्त सदस्य (लोक सभा)

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 27. श्री सुखदेव प्रसाद   | संसद सदस्य (राज्य सभा)                                  | 9. Chief Ports Officer, Maharashtra State, Bombay  | Representative of the Government of Maharashtra. |
| 28. श्री मन्मथ मिश्र, भवैतिक सचिव, भारतीय नाविक गृह समिति, मसजिद बस्तर, साईरिग रोड, बंबई-9।  | } नाविकों के कल्याण में रखने वाली सोसाइटी के प्रतिनिधि। | 10. Captain K.K.S. Kumaran, Director of Ports and Inland Water Transport, Karwai.  | Representative of the Government of Karnataka.   |
| 29. श्री के. वी. सुगवानेश्वरन, सचिव, नाविक गृह समिति, नाविक कल्याण कार्यालय, मरीन हाउस, कलकत्ता-22                                 |   | 11. Shri P. N. Batra, Director, Marine Department, Calcutta Port Trust, Calcutta.  | Representative of the Calcutta Port Trust.       |
| 30. उप-महानिदेशक नौवहन, नाविक कल्याण के प्रभारी (पदेन)   |   | 12. Shri M. K. George, Harbour Master, Cochin Port Trust, Cochin   | Representative of the Cochin Port Trust.         |
| 31. श्री के. के. खडिलकर, आनन्द भवन, डा. गांधीरोड, पारसी कालोनी, दादर, बंबई-14।   | } गैर-सरकारी सदस्य                                      | 13. Captain P. Balaram, Deputy Conservator, Madras Port Trust, Madras.   | Representative of the Madras Port Trust.         |
| 32. श्री के. बी. जगदीश, 308, थम्बू चेटी स्ट्रीट, मद्रास-600001।  |   | 14. Captain P. D. Gupta, Deputy Conservator, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.  | Representative of the Visakhapatnam Port Trust.  |
| 33. कप्तान बी. एल. बत्रा, माल प्रयोक्ता भारतीय मास्टर नाविक कंपनी सिंधिया स्टीम नवीगेशन कंपनी लि. के प्रतिनिधि सिंधिया हाउस, बंबई। |   | 15. Captain R.D. Kohli, Executive Director, Shipping Corporation of India Limited, Shipping House, Madam Cama Road, Bombay-400021. |  |

[एफ नं० एम डब्ल्यू एस (72)/76—एम० टी०]  
श्रीमती बी० निर्मल, प्रवर सचिव

### MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 29th September, 1977

#### MERCHANT SHIPPING

**S.O. 3321.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 218 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with Rules 3 and 4 of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, the Central Government hereby constitutes, for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the National Welfare Board for Seafarers, consisting of the following members namely :—

#### CHAIRMAN

- The Minister incharge of (Ex-officio) Shipping

#### MEMBERS

- The Director General of Shipping, 'Jahaz Bhavan', Walchand Hirachand Marg, Bombay-400001. Member (ex-officio)
- Joint Secretary dealing with Seamen's Welfare, Ministry of Shipping and Transport, New Delhi.
- Assistant Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport—representative of the Ministry of Finance (Department of Expenditure). \* \* \*
- Shri Ashok Narain, Deputy Secretary, Ministry of Labour, New Delhi.
- Shri S. Srinivasan, Deputy Secretary in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
- Shri R.K. Bhudhbhatti, Director of Ports, P.W. Department, Gandhinagar. Representative of the Gujarat Government.
- Captain P.K.R. Nair, Director of Ports, Kerala State, Trivandrum. Representative of the Government of Kerala.

- Captain B.D. Kataria, Director, Messers Seven Seas Transportation Limited, 15-A, Chander Mukhi, Nariman Point, Bombay.
- Shri T.S. Narayan, Deputy Manager, Messers Scindia Steam Navigation Company Limited, Scindia House, Bombay-400001. Representatives of Ship-owners.
- Shri N. Latif, Chairman, Owners or Agents Committee (Crews), 4, Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Bombay.
- Shri N. K. Sen, Chairman, Calcutta Liners' Conference (Crews), 16, Strand Road, Calcutta.
- Shri K. P. Kolah, General Secretary, Maritime Union of India, National Insurance Building, 204, Dr. D.N. Road, Bombay-400001.
- Shri Leo Barnes, General Secretary, National Union of Seafarers of India, 4, Goa Street, Fort, Bombay.
- Shri Yakub M. Serang, care of National Union of Seafarers of India, 4, Goa Street, Fort, Bombay.
- Shri Naresh Chandra Bharadwaj, Care of National Union of Seamen of India, 10/2-B, Kabirirtha Sarani, Calcutta-23.
- Shri Vilas Manjrekar, General Secretary, Jhahazi Mazdoor Union, Kamgar Sadan, Nawab Tank Road, Mazagaon, Bombay-400010.
- Shri B.P. Kadam
- Shri P. Thiagarajan
- Shri Sukhdev Prasad
- Shri Mastan Singh, Honorary Secretary, Indian Sailors Home Society, Masjid Bunder, Siding Road, Bombay-9.
- Shri K. V. Sugavaneswaran, Secretary, Nabik Griha Samity, Seamen's Welfare Office, Marine House, Calcutta-22.

Representatives of Seafarers

Member of Parliament, House of the People (Lok Sabha)

Member of Parliament, Council of States (Rajya Sabha).

Representatives of the Societies interested in the Welfare of Seamen.

30. Deputy Director General of Shipping, Incharge of Seamen's Welfare (ex-officio). Member Secretary.
31. Shri K. K. Khadilkar, Anand Bhavan, Dr. Ganti Road, Parsee Colony, Dadar, Bombay-14. } Non-official members.
32. Shri K. B. Jagdish, 308, Thambu Chetty Street, Madras-600001. }
33. Captain B. L. Batra, Cargo Superintendent, Scindia Steam Navigation Company Limited, Scindia House, Bombay. Representative of the Master Mariners of India.

[F. No. MWS(72)/76-MT]

SMT. B. NIRMAL, Under Secy.

**MINISTRY OF LABOUR**

New Delhi, the 5th October, 1977

**S.O. 3322.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Loyabad Colliery of M/s Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjoram District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd September, 1977.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD**

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

**Reference No. 6 of 1977**

(Ministry's Order No. L-20012/229/75/DIHA, Dt. 31-1-1977)

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Loyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited P. O. Bansjora, Distt. Dhanbad.

**AND**

Their Workmen.

**APPEARANCES :**

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate

For the Workmen—Shri D. Narsingh, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 15th September, 1977

**AWARD**

By a notice Ext. M-1 (which is the same as Ext. W-1) dated August 30, 1975, the Superintendent, Loyabad Colliery, which is owned by the Bharat Coking Coal Ltd. (hereinafter referred to as the B.C.C.L.), notified Gouri Lohar—the concerned workman—that "As you have attained the age of 60 years we hereby give you a month's notice on expiry of which your services will stand terminated on account of retirement. Accordingly, you will retire on and from 1st October, 1975." This notice was received by Gouri Lohar on September 4, 1975. He protested against his proposed retirement by a letter dated September 5, 1975 and repeated his protest by letter Ext. W-13 dated September 20, 1975 (which was sent by registered post, the acknowledgement being Ext. W-5). In Ext. W-13, he asserted that he had

not attained the superannuation age of 60 years and that he will attain that age in the next 10 to 12 years and, therefore, the notice should be withdrawn and he should be permitted to continue to work as Blacksmith till he reached the age of superannuation. This protest had, however, no effect on the B.C.C.L. and he was superannuated with effect from October 1, 1975.

2. Gouri Lohar represented his case to the A.L.C. Ext. W-2 contains the comments of the B.C.C.L. on the said representation. It mentions that Gouri Lohar was in the service of the colliery as a Blacksmith since the year 1942; that he had attained the age of superannuation of 60 years, according to the record of his age in the Register Form B; that the year of his birth, as recorded in the register Form B, stood corroborated by his Service Records and the Identity Card Register maintained by the previous owner; that if he had any complaint against his recorded age, he should not have signed the register form B, and that his contention that he was only 50 years of age at the time of his superannuation was wrong. The conciliation proceedings ended in failure. The dispute thus is whether the action of the management of Loyabad Colliery in superannuating him with effect from 1st October 1975 is justified? If not to what relief is he entitled?

3. It is the admitted case of both parties that the age of superannuation for a Blacksmith, is 60 years.

4. The point in dispute is purely a question of fact. I would first like to comment on the oral evidence in this regard. MW-1 Bansh Bahadur Singh is a clerk in the Welfare Office of the colliery. MW-2 Krishna Mohan is Assistant Personnel Manager, Area No. V, under which area Loyabad Colliery is situate. None of them has any personal knowledge about the date or year of birth of Gouri Lohar. Ordinarily also, they are not expected to have any such personal knowledge. Bansh Bahadur Singh is in the Loyabad Colliery only since 1971 and Krishna Mohan only since 1974. Gouri Lohar is said to have entered service in 1942 and it is obvious that MWs. 1 and 2 can have no personal knowledge about his real age. They have, therefore, rightly based their evidence on documents. WW-1 Gouri Lohar has deposed that he was only 50 years old at the time of his superannuation, and it is wrong that he attained the age of 60 years on October 1, 1975. He is unable to state if he joined service in 1942 or as to what was his age when he started service, and as to whether he was retired after having put in 33 years service. It is again apparent that no reliance can be placed upon his sworn testimony. He is a highly interested witness and knows only this much that he was 50 and not 60 at the time of his superannuation. He does not know the year in which he entered service or his age at that time. He does not know if he was superannuated after 33 years of service. His counsel requested me to look at him while he was present in the Tribunal, and at his photograph Ext. W-12 and form an opinion myself as to his age. Physical appearance, however, is very deceptive. A comparatively young man may look older and a comparatively old man may look younger. Photographs are still more deceptive. It is very risky for a Tribunal to hazard an opinion about age on the basis of its visual observations. The oral evidence, therefore, does not satisfactorily establish that Gouri Lohar was 50 or 60 at the time of his superannuation.

5. When a question of determination of age arises, usually it is established by the production of written admissions of deceased relations, horoscope, birth register, school records, medical certificate supported by reliable oral evidence.

6. The oral evidence has already been noticed above. Gouri Lohar has stated that he signs his name only but was not educated in any school. He has no horoscope and no written admissions of close relations; and has also not filed a copy of the birth register. Indeed, he has not produced any documentary evidence whatsoever in proof of his age, except two which I will now consider. Material Ext. I is a certificate said to have been granted by Dr. B. N. Singh on September 16, 1975 and Material Ext. II is a certificate said to have been given by Dr. S. P. Sinha on October 21, 1975. Gouri Lohar was able to prove his signature only on Material Ext. II. He is illiterate and was unable to prove the two medical certificates. These certificates, therefore, cannot be taken into consideration at all, and more so because the two experts were not examined as witnesses

to afford an opportunity to the B.C.C.L. to test the reliability of the certificates. Thus, there is no documentary evidence to show on behalf of Gouri Lohar that he had not attained the age of 60 years on October 1, 1975 or that he was only 50 years of age at the material time.

7. The B.C.C.L. has relied upon Exts. M-3 and M-4 to prove that Gouri Lohar would have attained the age of 60 years on October 1, 1975. Ext. M-3 is the Register Form B. The name of Gouri Lohar appears at serial No. 776 in this Register. In column No. 4, his age is recorded as the year 1915. The date of commencement of his service, as recorded in col. No. 7, is 1942. This entry is signed by him in Col. No. 7. The contention of the learned counsel for the B.C.C.L. is that this is a statutory register maintained under Sec. 48(1) of the Mines Act read with Rule 77 of the Mines Rules and should carry great weight. MW-2 Krishna Mohan has deposed that Gouri Lohar was superannuated because Ext. M-3 shows that he had reached the age of superannuation. MW-1 Bansh Bahadur Singh has proved this Register. He has deposed that the entry concerning Gouri Lohar is in his handwriting and that the entry was made on the basis of the information given to him by Gouri Lohar and that he signed the entry in his presence. I am not prepared to accept the evidence furnished by Ext. M-3 as conclusive. When the mine was nationalised, there was statutory direction requiring the Custodian to seize all records from the previous owner and I must take it that that statutory requirement was obeyed and fully complied with. That being so, the Register Form B, the Service Records of each workman, and the Identity Register must have been seized and must be in the custody of the B.C.C.L. In a large number of cases, the evidence produced is that after take over, or after nationalisation, the B.C.C.L. prepared a fresh Register Form B. This was done on the basis of the previous Register Form B. It was admitted in Ext. W-2 before the A.L.C. that the Service Records maintained by the previous owner were in the custody of B.C.C.L. The previous Register Form B has not been produced before me, and the new register is usually a copy of the old one with the necessary additions and alterations by adding the names etc. of new hands and deleting the names of those who have gone out of service. Bansh Bahadur Singh admitted that Ext. M-3 was prepared in 1972. He has further admitted that an entry in Register Form B is made when a workman is appointed initially. It appears to me that this must be so because as and when one is appointed initially, his name is bound to be entered in the statutory register Form B giving his name, his father's name, his age, his date of appointment, the nature of his employment etc. etc. These particulars would be ascertained then from the workman who is appointed and not every time that a new register is prepared. Bansh Bahadur Singh joined the Loyabad Colliery in 1971 while Gouri Lohar had joined it more than two decades earlier. I do not understand why Bansh Bahadur Singh would ask him over again about his particulars when all the particulars would be found in the previous register. Besides, even though he asserted that the entire entry is in his own handwriting, that does not appear to be correct because several inks and pens have been used, and the handwritings also appear to be in different hands. WW-1 Gouri Lohar has deposed that the particulars mentioned in Ext. M-3 are signed by him but the contents were never explained to him when the entry was made. He admits the correctness of all the particulars given, except the entry regarding his birth. Ext. M-4 is the Identity Register. I need not give the details of the entry at serial no. 154. It repeats the year of birth as 1915 and the date of employment as 1942. It is not signed by Gouri Lohar. Bansh Bahadur Singh deposed that an identity card containing all the particulars mentioned in Ext. M-4, was issued to Gouri Lohar and his signature was obtained in token of receipt, but when he was confronted with the register, he had to admit that his signature was missing. Gouri Lohar has denied that any identity card was issued to him. I must accept his evidence when the register does not contain his signature acknowledging receipt of the identity card. These are the only two documents on which reliance has been placed. It should have been apparent to the B.C.C.L. that when the notice was issued what was required was its own satisfaction about the age of Gouri Lohar but when that fact was challenged and an industrial dispute has been raised as to what is his age it is my satisfaction which is material. The B.C.C.L. was, therefore, under an obligation to place all the material documents before me, namely, the previous Form B Register of the time of the previous owner the previous service records of Gouri Lohar and any other material docu-

ment to show that its satisfaction was a justified satisfaction. Since those documents have not been filed, I am reluctant to accept Ext. M-3 and M-4 as conclusive on the matter.

8. Ext. M-5 is a circular issued by the Chief, Industrial Relation and Personnel, B.C.C.L., on January 6, 1973. Paragraph 2(v) mentions that "in respect of record of age the same recorded in the P.F. records should be taken as criteria. In case any representation is made against this the same may be examined and settled." This circular regulates the procedure for superannuation. The directive given is that in calculating the age of superannuation, the basic record to be taken into consideration is the P. F. record. However, if the workman challenges the accuracy of that record, then the matter must be examined and settled. Krishna Mohan has deposed that this record was consulted before the notice of superannuation was issued. I have no reason to discard his evidence. He must have consulted the record. However, the age has been challenged by the workman. The B.C.C.L.'s satisfaction, therefore, should have been made by satisfaction also. The P.F. record should have been produced before me to show as to what is the age recorded therein but this has not been done. No attempt has been made to satisfy me on the basis of that record that Gouri Lohar had attained the age of superannuation and no reason is forthcoming as to why that record has not been produced. Again, as soon as Gouri Lohar received the notice, he challenged that he had not attained the age of superannuation. No attempt was made to examine and settle the dispute before October 1, 1975 and he was made to retire automatically on that date. This was not proper. Either six months notice should ordinarily be given so that there is ample time for both parties to arrive at a settlement about the age of, if one month's notice was given, as is the case, then the B.C.C.L. should have settled it by September 30, 1975.

9. It was contended by the B.C.C.L. that repeated offers were made to Gouri Lohar to present himself for examination by an independent Medical Board consisting of Superintendent, Loyabad Central Hospital, one Doctor from Central Government Hospital at Dhanbad and the third Doctor from the District Hospital, Dhanbad but he persistently refused to appear for medical examination. All these offers, however, were made long after retirement. Ext. M-6 shows that such an offer was made on May 5, 1976. Ext. W-4 is another offer dated July 10, 1976. Before the R.L.C. also, the B.C.C.L. made the same offer on December 11, 1976 but Gouri Lohar backed himself out. He has denied that any such offer was made at that stage. But that does not appear to be correct in view of the proceedings Ext. M-7. MW-2 Krishna Mohan has also deposed that such an offer was made before the R.L.C. but Gouri Lohar did not accept it. He stands supported by Ext. M-7. It is clear, therefore, that B.C.C.L. made an attempt to settle the dispute some months after superannuation by inviting Gouri Lohar to subject himself for examination by a Medical Board but Gouri Lohar declined to do so. It was argued that an inference should, therefore, be drawn that he so declined because he was sure that the verdict would go against him. That inference is a possible inference but is not conclusive. Needless to mention that the evidence of a Medical man, however, eminent, is ordinarily a matter of mere opinion. Human judgment is fallible, and human knowledge is limited and imperfect. Medical evidence as to age is from its very nature based on conjecture and cannot be safely relied on to determine with precision the exact age of a person. True, ossification test may be a more sure test basis than the opinion of a medical expert, but cannot be regarded as conclusive and particularly so when ossification generally stops after a particular age. I do not mean to say that the idea of a Medical Board should be eschewed but it should be given a secondary importance. The main authentic document would be the certified copy of the Birth Register. The birth of every new born is recorded at Police Stations or in Chowkidar's Book etc. A certified copy of Birth Register can be produced and evidence can be taken as to how many sons a particular man had, what their names were, what was their seniority interse. when they were born, and the various birth certificates will establish their individual dates of birth.

10. There are three reasons why I cannot confirm the order of B.C.C.L. Firstly, because the various documents on the basis of which it reached its satisfaction, have not been produced before me. Secondly because, the directive of the Chief, Industrial Relations and Personnel was not followed; and thirdly, the Register Form B only mentions the year of birth as 1915 and not the date of birth, or that it was Octo-

ber 1, 1915. Gouri Lohar might will have been born on 31-12-1915 as that date would also fall within the year 1915. No basis has been given as to how the conclusion was reached that he was born on October 1, 1915.

11. I trust that the most just and proper manner of determining the age of Gouri Lohar would be to direct him—

(a) to file an affidavit mentioning—

(i) the names of his brothers, whether alive or dead, if any.

(ii) their places and his own place of birth, together with particulars in respect of Post Office, Police Station, District and State.

(iii) their, and his own date of birth and year.

(b) to file certified copies of their and his own Birth Register, and

(c) to lead such other oral and documentary evidence, as he may consider necessary, and to connect the Birth Registers with the respective persons whose dates of birth are recorded therein.

12. The Superintendent of the Colliery should show to Gouri (i) Service Records pertaining to him, (ii) the present Register Form B and the Register Form B of the time of the previous owner of the mine and (iii) the P. F. Records maintained at the colliery and certified copy of such record maintained in the P. F. Commissioner's office and (iv) the Identity Register.

13. If necessary, Gouri be required to appear before a Medical Board consisting of one Doctor of the Central Govt. Hospital in Jagjiwan Nagar, one Doctor of the District Hospital, Dhanbad and one Doctor of the Colliery.

14. On the totality of all this evidence, the Superintendent should review his order about the date of superannuation.

15. My award is that Gouri shall file the affidavit mentioned in paragraph 11 before the Superintendent, within one month of the publication of the Award and also comply with clauses (b) and (c) of paragraph 11 within a reasonable time thereafter. The Superintendent shall comply with paragraphs 12, 13 and 14 of the Award. He shall pass his final orders, on the basis of the result of his findings.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

[No. L-20012/229/75-D III A]

New Delhi, the 5th October, 1977

**S.O. 3323.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dharma Band Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Malkera, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th September, 1977.

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 11 of 1976

(Ministry's Order No. L-20012/115/76/DIIIA, dated, 27-10-76)

### PARTIES :

Employers in relation to the management of Dharmaband Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Malkera, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

### APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Narsingh, Advocate, with Shri J. D. Lall, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 24th September, 1977

### AWARD

Bisarjan Bhar and Hiyati Mia were both Loaders in the Dharmaband Colliery. The chargesheet Ext. M-1 dated May 7, 1975 was served on Hiyati Mia and the chargesheet Ext. M-14 of even date on Bisarjan Bhar. The charge against both of them was couched in identical terms, namely, that at about 8.30 a.m. on April 25, 1975, they, and a few other workmen, went to the office of C. P. Singh, the Colliery Manager, and without any reason or provocation, started shouting and when C. P. Singh asked them not to shout they dis-obeyed him, and pointing their fingers towards Sadan Singh, the Asstt. Colliery Manager, said : "AAP FALL BACK KEYON NAHIN DENGHEY. AAP KO DENA HOGA, AGAR AAP HAMARA FALL BACK KATENGHEY TO HAM BHI AAP KA HATH PAIR KAT DENGHEY." At this stage, C. P. Singh intervened and made efforts to pacify them but thereupon they again started shouting in loud tones and addressing their co-workers said : "YEH LOG DHANDHLI KARTEY HAIN. AB PHIR MAR PEET KARNE KE BINA KAM NAHIN HOGA. CHALO KAL PHIR AKAR JO KUCCH BHI BACHA HAI KARENGE." They were then asked to go out of the office but they did not obey and continued to shout for about half an hour and in that manner they did not allow C. P. Singh to do his normal work. They were, therefore, charged with the commission of the misconducts of wilful insubordination and dis-obedience under Standing Order No. 29(c); riotous, disorderly and indecent behaviour under Standing Order No. 29(e); causing wilful damage to work in progress under Standing Order 29(f), threatening their superiors under Standing Order 29(r) and preaching of and inciting violence under Standing Order 29(t).

2. Ext. M-2 and Ext. M-15 dated May 12, 1975 are the replies of Hiyati Mia and Bisarjan Bhar respectively. The replies are identical and are to the effect that the charges against them were false, concocted and motivated to victimise them as they were active members of the Bihar Colliery Kamgar Union and as such eye-sores to the management. They alleged that they had gone to C. P. Singh's office to protest against the unjustified deduction of fall back wages in a democratic and orderly manner but their protest was mis-understood, and the falsity of the charges will further appear from the belated issue of the chargesheets.

3. D. Biswas, the Personnel Officer, was appointed Inquiry Officer. He held separate domestic inquiries against the two workmen. C. P. Singh and Sadan Singh gave their depositions against Hiyati Mia, and Hiyati Mia examined himself and Zahir Mia in his defence. C. P. Singh, Sadan Singh and K. P. Singh gave their depositions in the separate domestic inquiry against Bisarjan Bhar, and Bisarjan Bhar examined himself alone in his defence. D. Biswas submitted his inquiry report Ext. M. 12 against Hiyati Mia on December 26, 1975 and a separate inquiry report Ext. M-32 against Bisarjan Bhar on January 12, 1976. He held that the charges under Standing Orders Nos. 29(c) and 29(f) were not established against either of them but the remaining three charges were fully established against both of them. The colliery Manager

proposed the punishment of dismissal of both the workmen and the same was approved by the General Manager by his order Ext. M-34 Dated January 21, 1976. The Colliery Manager then issued the formal order of dismissal Ext. M-3 against Hiyati Mia and Ext. M-33 against Bisarjan Bhar on January 22, 1976, dismissing both of them from January 24, 1976.

4. The learned counsel for the management desired that it be decided as a preliminary matter, as to whether or not the domestic inquiry was fair and proper. That matter was decided on May 30, 1977 and it was held that the two domestic inquiries were not fair and proper. In view of that decision of the Tribunal, both sides have led evidence on merits in the Tribunal itself.

5. There is no controversy between the parties that the questions whether the three charges are established or not and the punishment of dismissal is justified or not, have to be decided on the basis of the evidence taken by the management at the inquiry and the proceedings of the inquiry, and also on the basis of the further evidence led by them before the Tribunal.

6. The management has examined MW-2 C. P. Singh, the Colliery Manager; MW-3 Sadan Singh, the Asstt. Colliery Manager; and MW-4 U. P. Singh, the Colliery Personnel Officer in support of the charges. The workmen have examined themselves—Hiyati Mia as WW-1 and Bisarjan Bhar as WW-2 to controvert the evidence given by the management.

7. C. P. Singh has stated that he was sitting in his office room on April 25, 1975 along with Sadan Singh and U. P. Singh, when, at about 8.30 a.m., Hiyati Mia and Bisarjan Bhar, and a few other workmen, entered the room and Hiyati Mia raised the question of the allotment of a house to him on the ground that till then he had been staying at the house of a friend of his at Malkera Choitudih but had now brought his family also and should, therefore, be provided with an accommodation in the colliery itself. His statement is further to the effect that he informed Hiyati Mia that no accommodation could be provided to him immediately but houses were under construction and as soon as these were ready, allotment will be made and he should take his chance in the queue then. After this talk, Bisarjan Bhar pointed his fingers towards Sadan Singh and raised the question of non-payment of his alleged outstanding fall-back wages. While raising his problem, he told Sadan Singh: "AAP KYON HAMARA FALL BACK NAHIN DENGEY. AAP KO DENA HOGA. AGAR AAP HAMARA FALL BACK KATENGEY TO HAM BHI AAP KA HATH PAIR KAT DENGEY." The witness informed Bisarjan Bhar that a claim for fall-back wages is not met straightaway but has to follow compliance with the procedure. He also told him that the procedure was that he should make an application and his claim will then be considered on merits. At this stage, however, Hiyati Mia also repeated the same words verbatim which had been earlier used by Bisarjan Bhar. The witness told both of them that that was the wrong way to represent their case and it was not going to solve their problem. Bisarjan Bhar then turned towards the witness and said: "AAP BHI BAHUT DHANDHLI KARTE HAIN. AB HAM LOGON KO KUCHH KARNA HOGA." Hiyati Mia added to this by saying: "AB BILA MAR PEET KEY KAM NAHIN CHALEGA." The witness then told them that their shouts and threats were not going to solve their problems and they better went out from the room. In spite of this, they stayed for sometime more and kept on shouting. Thereafter, while going away, they said: "AB CHALO AAJ JO KUCHH BACHA HAI KAL DEKHENGEY." The witness has admitted that the claim for fall-back wages related to Bisarjan Bhar only and Hiyati Mia had not put forward any such claim. In cross-examination, he further admitted that neither Hiyati Mia nor Bisarjan Bhar had used any abusive words; nor did any of them assault any of the three officers present in the room, and none of them turned up next day also to execute their threats. He further admitted that at times when temper rises, serious threats are uttered which are never intended to be implemented, but the previous atmosphere of the colliery had been such that even such idle threats could materialise. Sadan Singh has deposed that Hiyati Mia and Bisarjan Bhar, with 20 or 25 others, came into the room, and Hiyati Mia raised the question of the allotment of a house to him. C. P. Singh told Hiyati Mia, that a house cannot be given in 2 or 3 days, that houses were under construction and when these

were ready, one house would be given to him also. Hiyati Mia, however, said that the house must be given that very day; or else he will not leave the room till it was given. The battle was then taken up by Bisarjan Bhar who rolled his red eyes towards the witness and said that he must pay his fall-back wages. He also said: "MSRA FALL BACK WAGES DENA HOGA. KYON NAHIN DEGA. NAHIN DEGA TO AAP KA HATH PAIR KAT DENGEY." Hiyati Mia repeated the same threat. C. P. Singh then told them that that was not the way to make a demand and they should make written applications which would then be considered by him. Upon this, Bisarjan Bhar said: "AAP BHI DHANDHLI KARTEY HAIN. AISE KAM NAHIN CHALEGA. KUCHH KARNA HOGA." Hiyati Mia repeated these words and said: "PHIR MAR PEET KARNA HOGA. BILA MAR PEET KEY KAM NAHIN CHALEGA." C. P. Singh made efforts to pacify the two by saying that nothing would turn on the basis of the manner of their talk; but his advice had no effect on them. They continued to do "HALLA GULLA" for sometime more. Thereafter they went away saying "AAJ CHALO. JO KUCHH BACHA HAI KAL KARENGEY." His cross-examination shows that the first to talk was Hiyati Mia whose demand was for a house, and the next to talk was Bisarjan Bhar whose protest was for non-payment of his fall-back wages. However, the witness says that Hiyati Mia also supported the demand for fall-back wages. He has denied that any threats were not given. He has also denied that the talk took place in a peaceful manner. U. P. Singh has deposed that Bisarjan Bhar, Hiyati Mia and 20-25 persons came into the room. Hiyati Mia asked C. P. Singh to provide him with an accommodation as his family had arrived. He also represented that he was residing in a rented house at Malkera colliery and he was in fear of danger to his life in coming to the colliery and going to his house after end of shifts in night time. He further told C. P. Singh that only 2 or 3 days earlier, some miscreants had surrounded him and he was, therefore, in great need of a house in the colliery premises itself. C. P. Singh told him that a house cannot be allotted on his mere asking, that houses were under construction and when these were ready he could apply in writing then and his application will be considered on merits. At this stage, Bisarjan Bhar addressed Sadan Singh and asked him why he was refusing to pay him fall-back wages. He further said: "AAP KO DENA HOGA. AGAR AAP FALL BACK KATENGEY TO MAI BHI AAP KA HATH PAIR KAT DOONGA." C. P. Singh told Bisarjan Bhar that no problem can be solved by a talk in that tone and manner. He also told Bisarjan Bhar that he should make a written application, which he (C. P. Singh) will consider on merits. Upon this, Bisarjan Bhar: "AAJ CHALO. PHIR BINA MAR PEET KAM NAHIN CHALEGA." Hiyati Mia addressed Bisarjan Bhar and said: "THEEK HAI AAJ CHALO. JO KUCH BACHA HAI KAL PURA KARENGEY." Then these two and their companions went away shouting. In cross-examination, he denied that they had made their demand only in a peaceful manner and had then dispersed.

7. Hiyati Mia's deposition is that he had gone to C. P. Singh's room to demand the allotment of a house and not for payment of fall-back wages, as he had no claim for any such wages. He, however, admitted that in his reply to the charge-sheet, it was mentioned that he had gone to demand the payment of fall-back wages but explained it by saying that the reply was wrong inasmuch as he had no such demand to make and further because, he being illiterate, had handed over the charge-sheet to someone in the union office for drafting his reply and had thereafter returned to his place of work and next day he had merely put his thumb impression on the reply without knowing the contents. This explanation of him appears to be correct. The evidence given in the domestic inquiry by the management's witnesses and the evidence given in the Tribunal, goes to show that Hiyati Mia's demand was only for a house and he had no interest in or concerning any fall-back wages and, as a matter of fact, he had raised no such demand also. In view of these admissions, it is obvious that the reply to the charge-sheet was incorrect and his stand is correct that he had gone merely to make a demand for the allotment of a house. He goes on to state that when he demanded the accommodation, C. P. Singh told him that a house will be allotted when those under construction were ready and he would get one when his turn came. He has further deposed that he told C. P. Singh that his family had arrived and he was in need of an accommodation in the colliery premises itself in order to remove the inconvenience caused to him in coming from and going back to Bhelatand, 3 miles away, where he was



then residing. He had denied that he abused C. P. Singh or Sadan Singh. He has denied that he repeated any threats or uttered any on his own. He has then deposed that he was the first to go inside the room and Bisarjan Bhar turned up 8 or 10 minutes later and he went away while Bisarjan Bhar was still present inside the room. In cross-examination, he has denied that he and Bisarjan Bhar had gone to the Manager's room together. He admitted that Bisarjan Bhar had asked Sadan Singh for his fall-back wages. He also admitted that Sadan Singh had told Bisarjan Bhar that he will check the colliery's books of account and if fall-back wages were due these will be paid to him. He says that he went away at this stage of the talk between Sadan Singh and Bisarjan Bhar and does not know what transpired between them after his departure. He has denied that the various threats were uttered by Bisarjan Bhar in his presence. He has also denied that he had repeated these threats or uttered any threats himself. Bisarjan Bhar has deposed that he went alone to the Manager's room to demand his fall-back wages. He found Hiyati Mia present there from before. In his presence, Hiyati Mia did not give any abuses or utter any threats to any officer. Hiyati Mia went away, while he himself continued to be present in the room. He demanded his fall-back wages from Sadan Singh. Sadan Singh told him that he will check the account books to ascertain if the wages were due, and if these were found to be due, payment will be made to him. He quietly went away after that. He has deposed that it is false that he had told Sadan Singh that if his fall-back wages were not paid, he will cut his hands and feet. He has also denied that he had uttered the threat that what remains to be done will be done next day. In cross-examination, he stated that when he reached inside the room, Hiyati Mia was demanding a house for himself. Hiyati Mia was saying that he had his residence at Bhelatand, that his family had arrived, that only 3 or 4 days earlier while he was going to the colliery in the night time some miscreants had attempted to rob him and had actually seized a watch from him and ever since then his life was in danger, and for these reasons he should be provided with a house. The witness says that he did not hear C. P. Singh telling Hiyati Mia that no house was immediately available, that houses were under construction, and one will be provided to him when the houses were ready. He is falsely telling a lie here. He must have heard the manager's reply because he was standing within 3 or 4 paces both of Hiyati Mia and C. P. Singh. In cross-examination, he has further denied that he had told Sadan Singh that his fall-back wages had been wrongly deducted. He has further denied that he had gone to make a protest against unjustified deduction. He was confronted with his reply to the charge-sheet which mentions that he had gone to protest against the unjustified deduction, but he says that that reply was wrong and the mistake occurred because he had merely put his thumb impression on it. It is obvious to me that he is telling a lie again. He had made damaging admissions in his statement in the domestic inquiry. He had stated there that "GHARIB KA IO PET KATTA HAI BHAGWAN BHI USKA PET KAT SAKTA HAI". He had stated in the domestic inquiry that it was possible for the management to obtain his thumb impression on the monthly pay-sheet, and then tell him that his wages had been paid. He had also stated that it was possible for the management to engage Goondas and have his feet and hands broken by them. He says that he had not made these statements, but when confronted, he is unable to give any explanations. He has denied that he uttered the various threats suggested to him in cross-examination. He has also denied that Hiyati Mia had repeated any threats.

8. I am not reproducing in detail the statements made by the various witnesses in the domestic inquiry; firstly, because there were two separate inquiries and it will not be proper to read the evidence in the inquiry against Hiyati Mia as evidence against Bisarjan Bhar or vice-versa. Secondly, besides some minor deviations here and there, the evidence in the domestic inquiry and before the Tribunal is practically the same.

9. On a consideration of the totality of the evidence on record, I am of the view that none of the three charges are established against Hiyati Mia. There was no community of interest between him and Bisarjan Bhar. One was in dire need of a house and the other was in an angry mood for

deduction of fall-back wages which he considered to be unjustified. The situation was such that one will go to beseech, to entreat, to make a request for a house and not to quarrel, while the other will go not to request but to protest, as he admitted also in his reply to the charge-sheet. He was labouring under a sense of grievance that fall-back wages were due and were not being paid arbitrarily. The management was telling him that he should make an application but he was arguing with the management. At least, he had deposed in his statement in the domestic inquiry that God will stop their ration if his fall-back wages were stopped; and going out of bounds of common courtesy, had said that C. P. Singh could even engage a Goonda and have his hands and feet broken. He had also said that he could even obtain his thumb impression on the wage-sheet and show a false payment. These facts show his mental attitude of insubordination and defiance of authority. It is true that he denies that he had made these statements, but the record is there to see. In his case, I do not see any reason why I should disbelieve the three important and responsible officers that he had uttered the threats attributed to him. So far as Hiyati Mia is concerned, his business was over as soon as his housing difficulty remained unsolved. He would have no reason to stay behind only to pick up a quarrel with the officers with regard to a matter with which he had no concern. No fall-back wages were due to him. He did not make any demand for such wages. These facts are admitted even by the management. Hiyati Mia says that he walked away after his own matter was over, and I see no reason to disbelieve him. The charge mentions that it is he who had demanded fall-back wages, it is he who had uttered the threats, and it is he who had taken an unreasonable attitude. The evidence given is that he made no demand for fall-back wages and he did not utter the threats. Again, the evidence given is that he only repeated the threats. There is a wide gap between the charge and the evidence. I find that the three charges against Bisarjan Bhar were established, namely, he uttered threats to his superior officers, that he preached violence and indulged in disorderly behaviour. None of the charges is, however, established against Hiyati Mia.

10. In the chargesheet, the three misconducts proved against Bisarjan Bhar are mentioned as misconducts under Standing Order No. 29(c), (r) and (t). It was argued that the misconduct of "threat" to superiors under 29(r) and "preaching of or inciting to violence under 29(t) are not misconducts at all under the Standing Order; and "disorderly behaviour" is misconduct under 27(5) and not under Standing Order No. 29 and, therefore, none of the charges can be taken to have been established. The evidence shows that the name of the colliery before nationalisation was Khas Dharmaband colliery, Ext. M-36 is the Standing Order. The misconducts are enumerated in Standing Order No. 27 and not in Standing Order No. 29. Likewise, threatening of superiors and preaching of or inciting to violence are not defined misconducts in Standing Order No. 27. That will, however, not mean that a wrong quoting of the number of the Standing Order will be material; nor will it mean that a workman can be punished only for a defined misconduct. There may be other kinds of behaviour which will invite punishment if such behaviour is detrimental to discipline. The facts constituting misbehaviours were mentioned in the chargesheet. Threatening superior officers and preaching and inciting violence are definitely misbehaviours. That being so, I am of the view that Bisarjan Bhar's dismissal was eminently justified.

11. My award is that the management has failed to establish any charge against Hiyati Mia. He shall be reinstated from January 24, 1976 and shall be paid his full back wages and other monetary benefits. My award further is that Bisarjan Bhar was rightly dismissed and is not entitled to any relief.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-20012/115/76-DIII]

New Delhi, the 11th October, 1977

**S.O. 3324.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Badjna Sub-Area No. VI of M/s C.M.A. Ltd., P.O. Nirsachatti, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 29th September, 1977.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3) AT DHANBAD**

**Reference No. 12 of 1977**

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Badjna Sub-Area number VI of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post office Nirsachatti, District Dhanbad.

**AND**

Their workmen

**APPEARANCES :**

On behalf of the employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

**STATE :** Bihar. **INDUSTRY :** Coal.  
Dhanbad, the 17th September, 1977

**AWARD**

This is a reference u/s 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 (hereinafter called the Act) by the Central Government Ministry of Labour under order No. L-20012/132/74-LRII/DILA dated 2-4-75. Schedule of reference is extracted below :

**SCHEDULE**

"Whether the management of Badjna Sub Area Number VI of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post office Nirsachatti, District Dhanbad, are justified in stopping the work of Sarvashri Jiwan Krishna Mazumder and Shymal Kumar Roy, General Clerks, Badjna Sub Area office with effect from 25-2-74? If not, to what relief the said workmen are entitled?"

2. The two workmen Shri Jiwan Krishna Mazumder and Shri Shymal Kumar Roy of Badjna Sub Area M/s. Coal Mines Authority Ltd. (at present Eastern Coalfields Limited) P.O. Nirsachatti District Dhanbad are involved. But in fact we are concerned only with Shri Jiwan Krishna Mazumder. Shri J. D. Lal appearing for the two workmen has submitted that he has no material in his possession to press the case of Shri Shymal Kumar Roy. Therefore, although in the reference there are two workmen, it is a case of only Shri Jiwan Krishna Mazumder that we are concerned with and with respect to Shri Shymal Kumar Roy the justifiability of the action of the management is not being challenged.

3. The dispute was sponsored by Bihar Colliery Kamgar Union before the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad, when it was complained to him that the management of Badjna Sub Area of Coal Mines Authority Limited had illegally stopped Shri Jiwan Krishna Mazumder and Shri Shymal Kumar Roy from work. The management was called upon to give its comments which it did on 23-3-74 with a copy to the union.

4. It appears that the union relied upon the agreement dated 27-11-72 in which the workmen in question were detailed as retrenched workmen and were to be given priority in employment. The management, however, took up the stand that it being not a party to the settlement was not bound by it and no list of workmen had ever been given to them from which it could be ascertained if the two concerned workmen were also affected.

5. The matter was discussed on several dates and the Assistant Labour Commissioner also visited the office of the Badjna Sub Area where he inspected some documents to

find out if the concerned workmen had ever worked in the office. It appears that it was only Shri Mazumder who put forward certain papers before him but Shri Shymal Kumar Roy was conspicuously absent.

6. The conciliation efforts failed as the parties could not arrive at a settlement and the Assistant Labour Commissioner sent a failure report dated 27-9-1974 to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, when the present reference was made.

7. A written statement has been filed on behalf of the employers stating therein that there is no such Sub Area known as Badjna Sub-Area No. VI of M/s. Coal Mines Authority Ltd. and therefore the reference which mentions Badjna Sub Area No. VI is not a competent one and it must be thrown out on that ground alone.

8. It is further said that no dispute much less any industrial dispute was ever raised by the workmen with the employers prior to their approaching the Assistant Labour Commissioner. The present reference which is on the basis of the failure report of the conciliation officer is clearly illegal and unwarranted inasmuch as letter to the conciliation officer by the union a copy of which was sent to the employers by the company can at best be considered a demand and not an industrial dispute between the workmen and the employers. On this ground also the reference is incompetent.

9. It is contended that none of the two workmen was ever employed in the Badjna Sub Area office in any capacity whatsoever and therefore the question of stopping them from work w.e.f. 25-2-74 does not arise.

10. It is also contended that in the course of the conciliation proceeding before the Assistant Labour Commissioner reliance was placed on behalf of the union on a tripartite settlement dated 23-11-72 in which besides other terms it was stipulated that those who would not like to work as miners or trammers would be kept in writing list and their cases would be discussed by the management and the union during the first week of February, 1972 for final settlement. As the Government of India took over the management of Shyampur colliery on 31-1-1973 there was no question of any discussion between the union and the custodian.

11. Case further is that in the memorandum no list of workmen who were affected by the settlement was appended and it was only at later stage that a list was given by the union which was undated and the two concerned workmen were shown to have been employed as Attendance Clerks. But when the records of Shyampur colliery was checked it transpired that they had never worked in that colliery in any capacity nor they were retrenched by the erstwhile owners. Two documents purported to have been written by Shri J. K. Mazumdar were brought before the conciliation officer to prove his alleged connection with the Badjna Sub Area office but they were written in connivance and in collusion with some subordinate staff which cannot bind the employers.

12. It is submitted that the concerned workmen have no case and the reference cannot be answered in their favour.

13. On behalf of the workmen written statement has been filed standing therein that they were working in Shyampur colliery and were permanent workmen of that colliery. Incline No. II of that colliery was closed by the erstwhile management as a result of which 105 workmen working in that incline and other clerks including them were proposed to be retrenched w.e.f. 3-10-72 and the Bihar Colliery Kamgar Union raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad, in regard to the proposed retrenchment of those 105 workmen. At the intervention of the Assistant Labour Commissioner an amicable settlement was arrived at whereby it was agreed to absorb those 105 workmen. By the time the management was taken over by the Central Government 11 of those workmen including these two remained to be absorbed and the union took up their case with the management. After prolonged correspondence and negotiations the two concerned workmen were re-employed by the Coal Mines Authority Ltd. as clerks in Badjna Sub Area Office w.e.f. 10-1-74 and worked till 24-2-74 when suddenly on 25-2-74 they were stopped without assigning any reason.

14. It is contended that the union made several representations to the management but nothing was done and the management was not justified in stopping them without assigning any reason and without proper order in writing. This action is violative of the certified standing orders and also of the principles of natural justice.

15. There is a rejoinder on behalf of the employers contending inter-alia that they relied on the settlement dated 27-11-72 for its true and correct import and whether the two concerned workmen were to be absorbed at all.

16. In other paragraphs of the rejoinder facts mentioned in the written statement have been reiterated and submission has been made that the concerned workmen are entitled to no relief.

17. There is also rejoinder on behalf of the employees. It is said therein that if by mistake Sub Area No. VI had been mentioned in the reference but if both parties are aware that the dispute relates to Badjina Sub Area the reference cannot be said to be incompetent.

18. It is further said that the workmen had raised dispute with the employers before the union raised industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad. Even if no such demand had been raised before the employers, on that ground alone the reference cannot be said to be incompetent.

19. Another point that has been taken is that according to terms of reference the workmen had worked in Badjina Sub Area office and, therefore, the employers are precluded from challenging the same.

20. On behalf of the workmen Shri Mazumder has examined himself. On behalf of the other workmen no documentary evidence has been produced nor he has examined himself. Exts. W-1 and W-2 are the signatures of Shri Mazumder on the dak despatch register, Ext. W-3 to W-3/2 are the letters sent by the Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union to the Deputy Custodian General, General Manager and the Area General Manager, Coal Mines Authority, respectively.

21. So far as the employers are concerned they have examined Shri R. C. Sharma who is now working in Badjina Sub Area and had participated in conciliation proceeding representing the management. Ext. M-1 is a copy of letter dated 24-6-74 from Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union to the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad which was forwarded to the management. Ext. M-2 is a letter dated 29-6-74 from the Assistant Labour Commissioner to the Sub Area Manager asking him to attend for discussion, concerning the above dispute. Ext. M-3 is the attendance register, Ext. M-4 form B register and Ext. M-5 is monthly pay sheet register.

22. At the time of argument besides the two legal objections that have been raised in the written statement of the employers, it has further been contended that the Badjina Sub Area being not a mine as defined in the Mines Act, the two workmen may be workmen u/s 2(s) of the I. D. Act, but the Central Government cannot be considered an appropriate government as defined in S. 2(a) of the Act and any reference made by it concerning the two employees of Badjina Sub Area Office is undoubtedly incompetent and this Tribunal is also not competent to entertain this reference.

23. Before taking up the facts involved in the case I would like to dispose of the law point first. So far as the above argument is concerned I find that there is a good deal of substance in it. The term 'mine' has been defined in S. 2(j) of the Mines Act and in S. 2(h) of that Act who would be considered to be employed in a mine has been elaborately defined. Appropriate government has been defined in S. 2(a) of the Act. The Central Government is the appropriate government only in regard to an industrial dispute concerning mines and other disputes referred to in clause (a)(1) of S. 2 of the Act. Taking the three definitions together although the two concerned workmen may come within the definition of S. 2(s) of the Act and may be entitled to all the rights under it, the special meaning of 'employment in relation to a mine' cannot be applicable to them. Therefore, the conciliation officer could not have sent a failure report to the Central Government and the latter could not have made a reference with respect to those two concerned

workmen who are not employed in relation to a mine and the Tribunal created by the Central Government has no jurisdiction to entertain a reference which concerns workmen who can't be said to be employed in a mine.

24. In this connection I may refer to the case reported in AIR 1966 S.C. 921-3 SCLJ 1800 (Sirajuddin & Co. vs. their workmen) wherein it has been held that the work which is incidental to or connected with mining operation must have some connection with or in relation to the mining operation themselves. Employees who perform work not connected with mining operation can't be said to be persons employed in the mine.

25. I may also refer to the case of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd. vs. P. Venkata Swamy and others reported in 1976 Lab. I.C. 1313. The garden mazdoors and malies attached to the bungalow, filed a petition under S. 33C(2) of the Act before the Labour Court, Dhanbad. Point was raised that those employees could not be held to be employed in a mine and therefore the Central Government was not the appropriate government and the Labour Court created by the Central Government had no jurisdiction to entertain that application. Their Lordships of the Patna High Court after considering S. 2(a) of the Act, S. 2(j) and (h) of the Mines Act and various authorities on the point including the one reported in AIR 1966 S.C. 921 came to the conclusion that the employment of the workmen in the bungalow was not an employment in a portion of a mine or in relation to a mine and the appropriate government in this case could not therefore be the Central Government. The Labour Court accordingly had no jurisdiction to entertain the application and to pass an order.

26. In the case before us the two concerned workmen claim to have been employed in the Badjina Sub Area Office which by no stretch of reasoning can be said to be a mine or connected with mining operation and therefore the Central Government is not the appropriate government to make a reference and this Tribunal which has been created by the Central Government has no jurisdiction to entertain the same.

27. The other point raised before me is that no demand having been raised before the employers, copy of the letter of the union sent by the Assistant Labour Commissioner to the management can't assume the character of an industrial dispute and therefore this reference is incompetent. In this connection Shri T. P. Choudhury, Advocate for the employers, has referred to the case of Sindhu Resettlement Corporation Ltd. and Industrial Tribunal of Gujarat and others reported in Vol. 7 SCLJ 792=1968 (16) F.L.R. 307. Shri J. D. Lal has made a passing reference to the case of the management of Radio Foundation Engineering Ltd vs. State of Bihar reported in AIR 1970 Pat. 295. Question arises whether on the basis of the decision in the Sindhu Resettlement Corporation Ltd. the reference should be held incompetent or whether reliance would be placed on Patna case. This Patna case was subsequently considered in the case of the management of Nand & Samonta Co. vs. Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad (unreported) and reliance was placed on the case of Sindhu Resettlement Corporation. This case has also been followed in AIR 1970 Delhi 60 (Feddere Lloyd Corporation (P) Ltd. vs. Lt. Governor) through Under Secretary, Labour and others.

28. In the Sindhu Resettlement Case no demand was made with the management regarding reinstatement and the only demand was in respect to retrenchment compensation. The conciliation officer as it appears from the judgment of the Supreme Court perhaps reported to the Government of India that an industrial dispute did exist relating to reinstatement and payment of wages. As no demand had been made with the management with regard to the reinstatement the Supreme Court came to the conclusion that there was no industrial dispute between the employers and the employees and the reference was incompetent. Their Lordships said that :

"a mere demand to a Government without a dispute being raised by the workmen with the employer, cannot become an industrial dispute".

29. In the instant case what I find is that there is nothing on record to show that any demand was made with the employers. Shri Mazumder has stated in cross-examination that

his representation was both written and oral and he has nothing at present to show that a written representation was made before the management. He does not say if there was any proof that he made any oral representation. On the contrary, MW-1 has stated that it was for the first time by the letter of the Assistant Labour Commissioner dated 29th June, 1974, Ext. M-2, that they had come to know about the dispute. That being the position, I have no hesitation to conclude that no industrial dispute was raised with the employees by the concerned workmen and consequently the Central Government could not have made any reference for adjudication to the Tribunal and that the reference which is before me at present is accordingly incompetent.

29. So far as the discrepancy in describing the Badjna Sub Area is concerned, that is of no importance in view of the fact that the parties are aware about the exact nature of dispute and there is no ambiguity on that score.

30. Coming to the oral evidence I find that it is a case of Shri Mazumder that he was appointed in Badjna Sub Area Office on 10-1-74 and worked till 24-2-74 when suddenly he was stopped from work without any notice w.e.f. 25-2-74. But he admits that he did not receive wages for the period, has no letter of appointment in the sub area office and did not put in his attendance during that period.

31. Record of the conciliation proceeding before the Assistant Labour Commissioner had been called for and produced. He visited the sub area office on 9-9-74 and checked the staff register but did not find his name there. He also did not come across any documentary evidence that he worked in the sub area office. He of course saw one appointment letter dated 21-1-74 which Shri Mazumder told him had been filled in by him. Exts. W-1 and W-2 were also produced before him and he found that Shri Mazumder had put his signature on the dak despatch register.

32. In the written statement there is a categorical assertion regarding his signature in the dak despatch register and in view of the admission of Shri Mazumder himself it is very difficult to hold that he was appointed in the sub area office in any capacity. The wage sheet register is on record and his name is not there. The form B register has been produced and his name is not there. The attendance register has been produced and his name is not there. Therefore, there is absolutely no material for a conclusion that he was appointed in Badjna Sub Area Office as alleged. In fact he admits that there is no paper in proof of his employment in Shyampur Colliery itself. It is true that his name appears in the list sent by Shri Keder Pandey to the Area General Manager on 6-9-73, Ext. W-3/2, but the utmost that can be inferred from it is that he was employed in the Shyampur Colliery and it cannot in any manner whatsoever establish that he was appointed in the Badjna Sub Area Office. The Eastern Coalfields Ltd. or its predecessor Coal Mines Authority Ltd. cannot be saddled with any responsibility for the act of the ex-employer. Under Section 7 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Central Government or the Government company cannot be liable for prior liabilities.

33. Taking into consideration all the available materials and the law on the point my considered opinion is that the reference is incompetent and the concerned workman have no case. Having not been employed in Badjna Sub Area Office as alleged, question of their stoppage does not arise. I don't agree with the contention that it is not open to the management to show that they have never been employed in the Badjna Sub Area Office and therefore there is no relationship of employer-employee. If what Shri I. D. Lal has contended is accepted, in that case on the terms of the reference itself an order for reinstatement with back wages would be passed. He has referred to the case reported in Vol 4 SCLJ-2307, Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. and workmen and others, in support of his contention that the Tribunal has no jurisdiction to go beyond the terms of reference and it must confine its adjudication to points of dispute referred and matters incidental thereto. Their Lordships have considered the provisions of S. 10(1)(a) and 10(4) of the Act and have come to the conclusion that it open to the parties to show that the dispute referred to was not an industrial dispute at all and it is certainly open to them to bring out before the Tribunal the ramification of the dispute. That being the position, certainly I cannot go beyond the terms of reference but the

management cannot be precluded from showing that the concerned workmen having not been in their employment ever, there can be no industrial dispute at all.

34. The management of the Badjna Sub area of M/s. Coal Mines Authority Post Office Nirsachatti district Dhanbad did not stop Shri Jiwan Krishna Mazumdar and Shyamlal Kumar Roy, General Clerks, Badjna Sub Area office w.e.f. 25-2-74 as they had never been employed in the office and on the other grounds indicated above the reference is incompetent.

This is my award.

S. R. SINHA, Presiding Officer  
[No. L-20012/132/74-LRII/DIIIA]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 13th October, 1977

S.O. 3325.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Bhilai Steel Plant (Mines) and their workmen.

#### BEFORE THE DEPUTY GENERAL SUPERINTENDENT, BHILAI STEEL PLANT AND ARBITRATOR

In the matter of arbitration of an industrial dispute under section 10A of the industrial disputes Act, 1947, between the management of the Bhilai Steel Plant and their employer Shri B. B. Danak, represented by Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC) about the alleged discrimination in the matter of promotion to executive post.

#### PARTIES :

- (1) Management of Bhilai Steel Plant, Bhilai  
and
- (2) Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC),  
Nandini, District Durg.

#### PRESENT :

Shri V. Subramony, Deputy General Superintendent, Bhilai Steel Plant, Bhilai, and ARBITRATOR.

For employer—Shri A. K. Chaudhuri, Dy. Personnel Manager Shri S. Balakrishnan, Asst. Personnel Manager, Shri S. K. Seth, Sr. Personnel Officer (Mines).

For workman—Shri C. R. Bakshi, Asst. Genl. Secretary, Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC), Nandini Mines, Dist. Durg. Shri D. K. Rao, Secretary, SKMS (AITUC) Nandini Mines, Dist. Durg. Shri B. B. Danak.

#### AWARD

An industrial Dispute between the management of Bhilai Steel Plant (Mines), Bhilai, and their workman represented by Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC), Nandini Mines, was referred to the undersigned for arbitration under Section 10 (A) of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government Notification No. L-26013/(2)/76 D. IV (E) dt. 5-5-1976.

Specific matters in the dispute :

‘Was any discrimination shown to Shri B. B. Danak, in the matter of promotion to executive post? If so, to what relief he is entitled to?’

Both the parties were requested on 11-6-1976 to submit their written statements and rejoinders with a copy to the opposite party latest by 30-6-1976. The parties jointly requested for extending the date for submission of written statements and rejoinders by 15 days, from 30-6-1976, which was granted. Both the parties submitted their statements on 15-7-1976 and jointly

requested for extending the date for submission of rejoinders and other documents by 10 days, from 15-7-1976, which was granted. The rejoinders were submitted by the parties on 26-7-1976. The first meeting was convened on 8-10-1976.

The Arbitration proceedings were held in my chamber in the presence of both the parties concerned in the case. As the proceedings could not be concluded for submission of the award within the prescribed period of 3 months, the period was extended up to 5th Aug '77 by mutual consent.

Shri B. B. Danak, born on 22-10-1922, who having a qualification of Intermediate, was serving as Chief Clerk in the Central Ordnance Depot under the Ministry of Defence while he applied for the post office Supdt., advertised by the Bhilai Steel Project on 20-8-1956. He was selected for the post of Head Asst. and joined Bhilai Steel Project on deputation on 25-1-1957 alongwith others. Shri Danak gave his consent to serve with the Company, i.e. Hindustan Steel Ltd., in August 57 and he was absorbed permanently in the Hindustan Steel Ltd. on 22-6-1960 and his lien with the parent department was terminated. Shri Danak was promoted as office Supdt. on 22-4-1960 and to the post of Section Officer on 1-5-1963.

In the year 1971, while Shri Danak was working in the Rajhara Iron Ore Group of Mines, he was superseded in the Matter of promotion to the post of Asst. Personnel Officer by his Juniors, and this has been the cause of the dispute. Since then Shri Danak has been superseded by several others who were junior to him, in subsequent promotions.

The Union's contention is that in the matter of promotion, Shri Danak has been discriminated against in as much as that his claim for promotion on the basis of seniority has not been granted by the Management. The Management's contention has been that as Shri Danak does not possess the requisite qualifications, i.e. a Bachelor's degree, for the post of an executive, he has not been promoted.

In support of their case, the Union has put up the following main arguments :

(1) Shri Danak was selected and joined Bhilai Steel Project on 25-1-1957 on transfer from the Ministry of Defence to the Ministry of Steel & Mines with his service conditions in tact as he was enjoying while in the Ministry of Defence. The Ministry of Steel & Mines, Department of Iron & Steel, gave full protection to his service conditions with lien in his parent department. Later, Shri Danak was asked for option for acceptance of his service with the Company within the framework of Company's rules with the clear understanding that the service conditions will be the same and will not be less favourable than enjoyed by him in the parent department.

(2) Prior to 1971 many persons in the same line of promotion and in other departments not possessing the requisite qualification, have been promoted to the executive post in the same organization even though the qualification stipulation was in existence since 1963.

(3) Even after 1971, Shri Danak's colleagues who were promoted prior to 1971 without the requisite qualifications have been further promoted within the executive cadre itself.

(4) Shri Danak was allowed to officiate in the executive posts several times during 1966 to 1970. However, this officiating has been denied to him subsequently even though there have been cases where officiating had been granted in executive posts to people who are not graduates.

(5) Management has used the prerogative to promote some non-graduates to the executive posts and this prerogative was not used in the case of Shri Danak even though his performance has been outstanding, which tantamounts to "discrimination".

The Management has put up the following arguments in favour of their stand :

(1) Shri Danak, when he joined Bhilai Steel Project on 21-5-1956 as Section Assistant, gave a letter of willingness that his services be transferred to the Hindustan Steel Ltd., with effect from 1-8-1957. In this letter he has clearly

stipulated that he agrees to be governed by the Company's rules in force from time to time in regard to leave, travelling allowance and other allowances, provident fund etc., on the presumption that this will not be less favourable than those existing at present. There has never been any commitment that there will be no change in the service conditions regarding promotion. A person joining a new organization cannot be covered by the promotion rules of his previous employers. Promotions which affect the interests of other co-workers also and the level of efficiency must conform to the requirements of the organization where an employee is working, and as such there cannot be any question of notional application of promotion rules of the previous employer.

(2) There have been few cases in which some persons who have been found to be exceptionally good have promoted to executive cadres even though they do not possess the requisite qualifications as at that time the organization was nascent and sufficient number of qualified personnel were not available. However, after the strict instructions from Head office in the year 1968, there has not been any case where a person who is not a graduate has been promoted to the executive cadre in that particular line of promotion. It was further stated that promotions before 1968 has not affected Shri Danak, as he has not been superseded at that time.

(3) There has not been any promotion from non-executive to executive cadre after 1971. There have been isolated cases of promotion within the executive cadre, i.e. from executive to executive cadres, which was within the executive power of the Management and this has not affected Shri Danak.

(4) The instructions regarding qualifications and eligibility of the person, is fully being taken into consideration even while a person is being given officiating chance to officiate against executive posts since 1971. There have been a few cases of officiating being granted to persons without the requisite qualifications earlier, but this has been for administrative convenience so as to facilitate continuity of work. But this has not affected Shri Danak and this rule is not applicable to Shri Danak only as he also was allowed to officiate prior to 1970 against executive posts.

(5) The management has right to change the rules to suit to the needs of the organization from time to time and this power, particularly concerning the executive posts, is not questionable. The Management at the same time has certain propogatives also and his prerogative which the management has used in promoting a few people without the requisite qualifications prior to 1968 or without the requisite qualifications within the executive cadre itself even after 1968, is to be understood as "prerogative". Not using the prerogative in the case of Shri Danak cannot be deemed as "discrimination."

In support of the various arguments, both the parties concerned have produced certain documents and were allowed to elaborate the various points concerned in these arguments in detail in the presence of the other party.

The observations of the undersigned on each of the arguments above are as follows :—

(1) It is agreed that the terms of service in the matter of promotion existing in a previous organization cannot be continued in the subsequent organization as the nature of work, system, priorities etc., will be entirely different. As such, the contention that Shri Danak should have been allowed to enjoy the rules with regard to the promotion of the Ministry of Defence during his tenure in Bhilai Steel Plant, is not valid.

(2) It is established that there have been cases in which persons without requisite qualifications have been promoted to executive posts up to 1968. The Management's contention that this has been done only because the organization was new and many qualified persons with sufficient experience were not available, does not fully establish the reason for the violation of a rule on qualifications which was in existence in 1963 itself. The Union had put forward a few cases in which the Management has been changing the rules which has resulted in promotion of a few people without the requisite qualifications while denying the same to a few others prior to 1968, which, in the opinion of the undersigned, should have been avoided. However, since these actions of the Management

prior to 1968 has not caused any supersession to Shri Danak and as his claim for promotion has arisen only in the year 1971, and as during the period 1968 to 1971 and beyond 1971 there has not been any case of promotion of any one in the particular line of promotion without requisite qualifications to the executive level there has not been any cause of grievance in the matter of promotion for Shri Danak.

(3) There have been cases in which persons without requisite qualifications, who were promoted to executive level prior to 1968, have been promoted to higher levels in the executive level itself even after 1971. However, this does not affect Shri Danak nor has caused any grievance to Shri Danak, as his claim for promotion is from non-executive to executive cadre which has arisen in 1971, when he became No. 1 in the Seniority list in the particular line promotion.

(4) Officiating arrangement in the organization, as it came out during the arguments, has not been always strictly as per rules, and the circumstances under which the rules could not be strictly followed in the matter of officiating, as brought out by the Management, is logical. It was established that in an organization having various units and having small groups looking after the office work in various units, it will not be always possible to strictly follow the rules as regards officiating. However, Shri Danak has not been singled out since 1971 as regards officiating is concerned, and as Shri Danak also was given chances to officiate before 1971 alongwith others, who

do not possess the requisite qualifications had not been granted officiating after 1971, there has not been any discrimination shown to Shri Danak.

(5) Any management has certain prerogatives and these prerogatives are to be judiciously used in exceptionally deserving cases consistent with the organizational needs. Denial of the use of this prerogative power of the management in a particular case cannot be deemed as "discrimination", as use of this prerogative in all cases defeats the very essence, efficacy and purpose of this prerogative power. Even this discriminatory power has not been used to promote any one in the L.O.P. since 1968, and as the claim for promotion for Shri Danak has come, only in 1971, he has no cause for grievance.

In view of the above, it is the considered opinion of the undersigned that there has not been any discrimination shown to Shri B. B. Danak in the matter of promotion to executive post, and as such is not entitled to any relief.

The Award is given accordingly in terms stated in the earlier para.

Given the Award under my Seal and signature the thirtieth day of July, 1977.

V. SUBRAMONY, Dy. General Suptt.

Bhilai Steel Plant, Bhilai.

and Arbitrator

[No. L-26013(2)/76-DIIB]

J. C. SAXENA, Under Secy.